

4/2



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

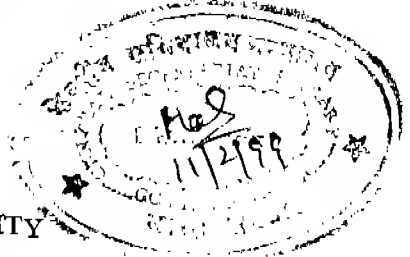
EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II—Section 1A

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]
No. 1]

नई दिल्ली, बुधवार, 16 जनवरी, 1997/26 पौष, 1918 (शक)

New Delhi, Thursday, January 16, 1997/Pausa 26, 1918 (Saka)

[खण्ड XXXIII
Vol. XXXIII]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1997/26 पौष, 1918 (शक)

दि तेजपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 1993 ; (2) दि कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन (अमेंड-मेंट) ऐक्ट, 1993 ; (3) दि पंजाब ग्राम पंचायत, समितीज एंड जिला परिषद् (चंडीगढ़ रिपील) ऐक्ट, 1994 ; (4) दि बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ ग्रंटरटेकिंग्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1994 ; (5) दि नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम) ऐक्ट, 1994 ; (6) दि कस्टम्स टैरिफ (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 ; (7) दि बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ ग्रंटरटेकिंग्स) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1995 ; (8) दि नेशनल हाइवेज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 ; (9) दि यूनियन इयूटीज आफ एक्साइज (डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट, ऐक्ट, 1995 ; (10) दि एडिशनल इयूटीज आफ एक्साइज (गुड्स आफ स्पेशल इंपोर्टेंस) अमेंडमेंट ऐक्ट, 1995 ; (11) दि पेमेंट आफ बोनस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 ; (12) दि जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन (नं० 2) ऐक्ट, 1995 ; (13) दि एप्रो-प्रिएशन (नं० 3) ऐक्ट, 1995 ; (14) दि एप्रोप्रिएशन (नं० 4) ऐक्ट, 1995 ; और (15) दि रिसर्व एंड डेवलपमेंट सेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 1995 : के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963, 1963 का 19 की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, January 16, 1997/Pausa 26, 1918 (Saka)

The Translation in Hindi of the following, namely:—
The Tezpur University Act, 1993; (2) The Consumer Protection (Amendment) Act, 1993 (3) The Punjab Gram Panchayat, Samities and Zila Parishad (Chandigarh Repeal) Act, 1994;
(4) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of

Undertakings) Amendment Act, 1994; (5) The Neyveli Lignite Corporation Limited (Acquisition and Transfer of Power Transmission System) Act, 1994; (6) The Customs Tariff (Amendment) Act, 1995; (7) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Amendment Act, 1995; (8) The National Highways (Amendment) Act, 1995; (9) The Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Act, 1995; (10) The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Act, 1995; (11) The Payment of Bonus (Amendment) Act, 1995; (12) The Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Act, 1995; (13) The Appropriation (No. 3) Act, 1995; (14) The Appropriation (No. 4) Act, 1995; and (15) The Research and Development Cess (Amendment) Act, 1995 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 45)

[1 जून, 1993]

भारत गणराज्य में तेजपुर में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उसके संबंधित या उसके आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चत्तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तेजपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1993 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रयुक्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द" से ऐसे प्रयोगों के कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं, जो अध्यापकों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द अभिहित किए जाएं ;

(ग) "प्रबन्ध-बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध-बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं ;

(च) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला महाविद्यालय अभिप्रेत है ;

(छ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्ययन केन्द्र हैं ;

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से संचार के किसी माध्यम, जैसे कि प्रसारण, टेलिविजन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारी-वृन्द हैं ;

(ग) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(घ) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या किसी संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती है;

(ङ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है जो महाविद्यालय नहीं है;

(च) "योजना और विद्या समिति" से विश्वविद्यालय की योजना और विद्या समिति अभिप्रेत है;

(छ) "योजना बोर्ड" से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है,

(ण) "प्राचार्य" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और जहां कोई प्राचार्य नहीं है वहां इसके अन्तर्गत प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उप-प्राचार्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति है;

(त) "मान्यताप्राप्त संस्था" से उच्चतर विद्या की ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(थ) "मान्यताप्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(द) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाया गया तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत है;

(ध) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय का विद्यापीठ अभिप्रेत है;

(न) "परिनियम" और "अध्यादेश" से तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(प) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किए जाएं;

(फ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित तेजपुर विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालय।

3. (1) "तेजपुर विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय तेजपुर में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे केम्पस स्थापित कर सकेगा।

(3) प्रथम कुलपति तथा प्रबंध-बोर्ड, योजना और विद्या समिति या विद्या परिषद् या योजना बोर्ड के प्रथम सदस्य तथा वे सभी व्यक्ति जो प्रागे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बने, जब तक वे पद पर बने रहते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है, इसके द्वारा "तेजपुर विश्वविद्यालय" के नाम से निश्चित शिर्षक के रूप में गठित किए जाते हैं।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाव लाएगा और उस पर वाव लाया जाएगा ।

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो बहुत ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना ; विश्वविद्यालय के शिक्षा कार्यक्रमों में मानविकी, प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान और वन विज्ञान तथा अन्य सहबद्ध विषयों में सविकसित पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना ; अध्यापन-अध्ययन प्रक्रियाओं, अंतर विषयक अध्ययन और अनुसंधान में नई पद्धति की अभिवृद्धि करने के लिए समुचित उपाय करना ; असम राज्य के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना ; और उस राज्य के लोगों की सामाजिक और आर्थिक वृद्धि को सुधारने तथा उनके कल्याण, उनके बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना होगा ; और विश्वविद्यालय अपने क्रियाकलापों का आयोजन करने में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना ;

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विनिर्दिष्टाएं प्रदान करना, तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर किन्हीं ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विनिर्दिष्टताओं को वापस लेना ;

(iii) निवेशबालू, अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना ;

(iv) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानव उपाधियां या अन्य विनिर्दिष्टाएं प्रदान करना ;

(v) दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से उन व्यक्तियों की, जिनके बारे में यह अवधारित करे, सुविधाएं प्रदान करना ;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा अशिक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(vii) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना ;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना ;

(X) प्रशासनिक, अनुसन्धान और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियाँ करना ;

(Xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त करना होना ;

(Xii) ऐसे केम्पस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएँ या अनुसंधान और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयाँ स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;

(Xiii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना ;

(Xiv) महाविद्यालय, संस्थाएँ और छात्र निवास स्थापित करना और उनको चलाना ;

(Xv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से उस प्रयोजन के लिए ऐसे ठहारा करता, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(Xvi) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुष्पकार्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएँ, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना ;

(Xvii) छात्राओं के आवास, अनुशासन और शिक्षण के बारे में ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(Xviii) सम्पागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की सविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान दे सकें ;

(Xix) परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(XX) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना ; जिसके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति है ;

(XXi) फीसों और अन्य प्रभारों का भाग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(XXii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध कराना ;

(XXiii) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता है, अधिकथित करना ;

(XXiv) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसे प्रवृत्त कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(XXv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना ;

(xxvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संपत्ति और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अन्तर्गत व्यास और विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, उसे धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना ।

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xxviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुवंशिक या सहायक हों ।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण असम राज्य पर होगा ।

अधिकारिता ।

7. विश्वविद्यालय सभी स्थितियों और पुरुषों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, पञ्चवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधि-पूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी आर्थिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानवेंड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे :

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पेशों के लिए खुला होना ।

परन्तु इस धारा की कोई बात, विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के दुर्बल वर्गों और विप्रेतता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

8 विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र (उस छात्र से भिन्न जो दूर शिक्षा पद्धति में अध्ययन कर रहा है) किसी छात्र निवास या होस्टल या ऐसी अवस्थाओं में रहेगा, जो अध्यादेश द्वारा विहित की जाएं ।

छात्रों के आवास ।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

कुलाध्यक्ष ।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत उसके प्रबंधाधीन महाविद्यालय और संस्थाएँ हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर एक या अधिक व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से प्रबंध बोर्ड का विचार अभिप्राय करने के पश्चात्, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह रिपोर्ट में वर्णित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निवेदन से, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाली किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षा, दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त में संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा ।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा, और विश्वविद्यालय को, कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे ।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्यादेशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जैसा उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है, वहां विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक्कदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में स्वयं हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में कराई जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधित की प्राप्ति पर, कुलपति, प्रबंध-बोर्ड को कुलाध्यक्ष के विचार तथा सलाह संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो।

(8) प्रबंध-बोर्ड, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष की वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है।

(9) जहां प्रबंध बोर्ड, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष, प्रबंध-बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या अध्यादेश पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और प्रबंध-बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परि-नियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह कुलसचिव से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

- (1) कुलाधिपति ;
- (2) कुलपति ;
- (3) प्रतिकुलपति ;
- (4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष
- (5) कुलसचिव ;
- (6) वित्त अधिकारी ; और

(7) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति

11. असम राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति, अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित ही तो, वह उपाधियों उपदान करने के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी कुलपति। जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्व-विद्यालय के किसी प्राधिकरण की इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रवृत्त है और अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राधिकरण को देगा।

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील, प्रबंध-बोर्ड से करे और तब प्रबंध-बोर्ड, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) यदि कुलपति की यह है रक्त कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रवृत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

13. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। प्रतिकुलपति।

14. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष।

15. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। कुलसचिव।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी । 16. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी । 17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण । 18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(1) प्रबन्ध बोर्ड

(2) योजना और विद्या समिति ;

(3) विद्या परिषद् ;

(4) योजना बोर्ड ;

(5) अध्ययन बोर्ड ;

(6) वित्त समिति ; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

प्रबन्ध-बोर्ड । 19. (1) प्रबन्ध-बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालय निकाय होगा ।

(2) प्रबन्ध-बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

योजना और विद्या समिति । 20. (1) विश्वविद्यालय की एक योजना और विद्या समिति गठित की जाएगी जो प्रबन्धनबोर्ड को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और विकास संबंधी क्रिया-कलापों से संबंधित विषयों पर सलाह देगी और विश्वविद्यालय के विकास की देखभाल, पुनर्विलोकन तथा उसे मानिटर करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान के स्तरमात्र का पुनर्विलोकन करती रहेगी ।

(2) योजना और विद्या समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(3) कुलाध्यक्ष बहु तारीख अवधारित कर सकेगा जिससे योजना और विद्या समिति विघटित होगी ।

विद्या परिषद् । 21. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी ।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

22. (1) योजना बोर्ड, जब भी गठित किया जाए, विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड
प्रधान योजना निकाय होगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी
शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

23. विद्यापीठों के बोर्डों का गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । विद्यापीठों के बोर्ड ।

24. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । वित्त समिति ।

25. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे । विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्न-लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :— परिनियम बनाने की शक्ति ।

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और उनका पदों पर बना रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का उद्बन्ध, सेवा समाप्ति और आनुशासनिक कार्रवाई की रीति है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शास्ति करने वाले सिद्धांत ;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थता की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा प्रबंध-बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग की स्वायत्त प्राप्ति प्रदान करना ;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केंद्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ;

(ठ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना ;

(ढ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जाएं ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो दूसरी अनुसूची में उपबणित हैं ।

(2) प्रबंध-बोर्ड समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परंतु प्रबंध-बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्राप्ति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उनका संशोधन नहीं करेगा और उनका निरसन नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर प्रबंध बोर्ड विचार करेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्तन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधार्ति कर सकेगा या उसे प्रबंध-बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा ।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विद्यमान नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाघ की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परंतु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकेगा, और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख जाएंगे ।

(6) पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि प्रबंध-बोर्ड ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, प्रबंध-बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित

कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परि-
नियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश बनाने
अध्यादेशों से निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के लिए उपबंध किया जा
सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम
दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों
के लिए अधिकृत किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष
उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान
करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की
परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने
वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियों, पुरस्कार और पुरस्कार
प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों,
परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके
कर्तव्य हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए
जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उसके लिए विशेष पाठ्यक्रमों
का विहित करना ;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है
उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं
और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अन्तर्गत
विद्वत्, निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति ;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन
में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके
कृत्य ;

(३) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा के ऐसे अन्य
निबंधन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं ;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का
प्रबंध ;

(त) कर्मचारियों की व्यथाओं को दूर करने के लिए किसी तंत्र
की स्थापना ; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के
अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं ।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलाध्यक्ष द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से प्रबंध-बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के, यदि कोई हैं, कार्य संचालन के लिए, जिनका इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा, विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध-बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे।

(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को उस तारीख की या उसके पूर्व भेजी जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र प्रबंध-बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतराल पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाग्रों की प्रति संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, कुलाध्यक्ष की प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाग्रों पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण प्रबंध-बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और प्रबंध-बोर्ड के संप्रेक्षणों को, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष की प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) कुलाध्यक्ष को दी गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाग्रों की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो उसे यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

32. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित सविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच सविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा, जिसमें प्रबंध-बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् अधिकरण, 1940 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निबेदन समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

33. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबन्ध-बोर्ड को अपील कर सकेगा और प्रबन्ध-बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थ्य की प्रक्रिया।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थ्य अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उल्लेख इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को, यथाशक्ति, लागू होंगे।

34. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रबन्ध-बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तब प्रबन्ध-बोर्ड उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

अपील करने का अधिकार।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

भविष्य और पेंशन निधियां।

1925 का 10

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

समितियों का गठन।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्य-वाहियों के कारण अविधिमान्य न होमा ।

सम्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण ।

विश्वविद्यालय के अधिलेख को साबित करने का ढंग ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण, अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ हैं ।

40. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सम्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई बाध या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्पूर्ण रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा स्थापित कर दी जाने पर, उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्रह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ली जाएगी और उसमें संबंधित मामलों और संश्लेषहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी ।

1872 का 1

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीव हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

43. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम प्रबंध-बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ;

(घ) प्रथम विद्या परिषद् और प्रथम योजना बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से छत्र वर्ष की अवधि की समाप्ति पर गठित किया जाएगा और उक्त दस वर्ष की अवधि के दौरान इन दोनों प्राधिकरणों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन धारा 20 के अधीन गठित योजना और विद्या समिति द्वारा किया जाएगा ;

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि वैसी रिक्ति न हुई होती तो, पद धारण करता ।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अवकाश दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो अल्पव्याप्त वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पड़ने की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेश या विनियम या उनमें से किसी का उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतरफ हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

पहली अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

1. विश्वविद्यालय, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास करेगा और उस क्षेत्र की समृद्ध विरासत के आधार पर, असम राज्य के लोगों की संस्कृति की और उसके मानव संसाधनों की अभिवृद्धि और समृद्धि का प्रयास करेगा। इस दिशा में वह,—

(क) असम राज्य की स्थानीय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं तथा विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अधिकांशतः स्नातकोत्तर स्तर पर, नियोजन-जनित और अन्तर विषयक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने का प्रयास करेगा।

(ख) उन क्षेत्रों में, जिनकी उस प्रदेश से विशेष और प्रत्यक्ष सुसंगति है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अन्वेषणोपरान्त प्रकट होने वाले क्षेत्रों में भी, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करेगा तथा अनुसंधान की अभिवृद्धि करेगा ;

(ग) राष्ट्रीय एकता और उस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन की और विशेष रूप से राज्य की विविध जातीय, भाषायी और जनजातीय संस्कृतियों की अभिवृद्धि करेगा ;

(घ) जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए और विशेष रूप से ऐसे असुविधाग्रस्त समूहों के लिए जो दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उच्चतर शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए दूर शिक्षा तकनीकों और आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा; सेवारत कामियों, विशेष रूप से स्कूल के अध्यापकों, चिकित्सा कामियों और विस्तारण कर्मचारियों के वृत्तिक ज्ञान और कौशल को बढ़ाएगा; और प्रौढ़ों के लिए जीवनपर्यन्त अध्ययन के अवसरों का उपबन्ध करेगा; और

(ङ) ज्ञान के नए क्षेत्रों में अध्ययन की अभिवृद्धि और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक नई पद्धति का, जिसमें अध्ययन के ढंग और गति के बारे में लचीलापन, पाठ्यक्रमों के संयोजन, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की प्राप्ति, परीक्षा के संचालन और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है, उपबन्ध करेगा।

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिमियम

कुलाधिपति

1. असम राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

कुलपति

2. (1) कुलपति की नियुक्ति खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे, तो वह नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का कर्मचारी या प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद् या योजना

और विश्वविद्यालय का सदस्य, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या विश्वविद्यालय से सहयुक्त किसी संस्था से सम्बद्ध नहीं होगा और तीन व्यक्तियों से से दो प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशित मिति का संयोजक होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु उक्त पांच वर्ष की अवधि का अवसान हो जाने पर भी, वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि जिस कुलपति की पदवधि का अवसान हो गया है, वह कुल मिलाकर एक वर्ष में अनुधिक की ऐसी अवधि तक जो उसके द्वारा विनिश्चित की जाए, पद पर बना रहेगा।

(5) कुलपति की उपलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति की केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और भूतल किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदवधि के दौरान बिना किराया दिए मुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अक्षरक्षण की बाबत स्वयं कुलपति को कोई प्रभार नहीं देता होगा।

(ii) कुलपति ऐसे सेवागत फायदों और भत्तों का हकदार होगा, जो प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन में समय-समय पर नियत किए जाएंगे।

परन्तु जहाँ विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उनसे सम्बद्ध किसी संस्था का कोई कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहाँ उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करने रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाने में उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था।

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा।

(iii) कुलपति ऐसी दरों में जो प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा लिया की जाए, यात्रा भत्ते का हकदार होगा।

(iv) कुलपति किसी कलेण्डर वर्ष में तीस दिन की दर में पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी की प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को पन्द्रह दिन की दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में अधिम रूप में उसे खाने में जमा कर दिया जाएगा।

परन्तु यदि कुलपति आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है, तो छुट्टी की अनुपातित सेवा के प्रत्येक संचालित मास के लिए ढाई दिन की दर से जमा किया जाएगा।

(v) कुलपति खंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संचालित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्द्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। इस अर्द्ध वेतन छुट्टी का उपयोग वित्तीय प्रमाणपत्रों के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा। यदि परिवर्तित छुट्टी का उपयोग किया जाता है तो अर्द्ध वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्द्ध वेतन छुट्टी से विकसित की जाएगी।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अभ्युपनिवेश रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अवस्थिता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या वर्तमान कुलपति अपने पद का कर्तव्य संभाल नहीं लेता ।

कुलपति की शक्तियाँ और कर्तव्य

3. (1) कुलपति, प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियाँ प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा । किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा ।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(6) कुलपति की प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

प्रतिकुलपति

4. (1) प्रत्येक प्रतिकुलपति, प्रबंध-बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु जहाँ कुलपति की सिफारिश प्रबंध-बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, वहाँ उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को नियुक्त करेगा या कुलपति ने प्रबंध-बोर्ड को किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा :

परन्तु यह और कि प्रबंध-बोर्ड, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो प्रबंध-बोर्ड विनिश्चित करे किन्तु किसी भी दशा में वह पाँच वर्ष से अधिक या कुलपति की पदावधि के अवसान तक, इसमें ने जो भी पहले हो, नहीं होगी :

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन, कुलपति के कर्तव्यों का, निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि का अवसान होने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या वर्तमान कुलपति अपने पद के कर्तव्य संभाल नहीं लेता ।

परन्तु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाता है और कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो प्रबंध-बोर्ड एक प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रतिकुलपति, कुलपति की नियुक्ति होते ही और अपना पद संभालते ही, उस पद को धारण नहीं करेगा ।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

कुलसचिव

5. (1) कुलसचिव की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंध-बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्ण-कालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलसचिव साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरदायी नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इसमें से जो भी पहले हो ।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव दण्डता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) (क) कुलसचिव की, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी जो प्रबंध-बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उस पर परिनिदा की या वेतन बढ़ि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बनाने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां कुलसचिव जांच के पूरा होने पर कुलपति की अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा।

परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबंध-बोर्ड को होगी।

(6) कुलसचिव, प्रबंध-बोर्ड, योजना और विद्या समिति, विद्या परिषद् और योजना बोर्ड का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों सामान्य भूत और अन्य ऐसी संपत्ति को, जो प्रबंध-बोर्ड उसके धारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

(ख) प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद्, योजना और विद्या समिति, योजना बोर्ड के और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले ;

(ग) प्रबंध-बोर्ड विद्या परिषद् योजना बोर्ड के तथा उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे ;

(घ) प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद्, योजना और विद्या समिति, और योजना बोर्ड के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करे ;

(ङ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार इंतजाम और अधीक्षण करे ;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध बाधों या कार्यबाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुस्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को स्थापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे ; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी प्रबंध-बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

वित्त अधिकारी

6. (1) वित्त अधिकारी, इस प्रयोजन के लिए गठित धन समिति की सिफारिश पर प्रबंध-बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वित्तिक प्राधिकारी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और अर्तों से होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि वित्त अधिकारी, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद धारण नहीं कर लेता है या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी गणता, अनुपस्थिति के कारण या किसी कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु उस समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी--

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संवर्धन में उसे सलाह देगा ; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

-(7) प्रबन्ध-बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी--

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को जिसके अन्तर्गत न्याय और विन्यास की संपत्ति है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आवंटित किया गया है ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको प्रबन्ध-बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर, और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपयोग्य अन्य सामग्री के स्टॉक की जाँच की जाए ;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा ; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था में कोई ऐसी जानकारी या विवरणियाँ मांगेगा, जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप में प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संचय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष

(1) विद्यापीठ के प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के प्राचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु संकायाध्यक्ष साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस पद पर नहीं रहेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी समय किसी विद्यापीठ में प्राचार्य नहीं है तो कुलपति या कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संकायाध्यक्ष, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है, तब तक उसे अपने मत देने का अधिकार नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष

8. (1) ऐसे विभागों की दशा में जिनमें एक से अधिक प्राचार्य हैं विभागाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर, प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा प्राचार्यों में से की जाएगी।

(2) ऐसे विभागों की दशा में जिनमें केवल एक प्राचार्य है, प्रबन्ध-बोर्ड को कुलपति की सिफारिश पर, प्राचार्य को या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त करने का विकल्प होगा :

परन्तु प्राचार्य या उपाचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतन्त्रता होगी।

(3) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(4) विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(5) विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

कुलानुशासक

9. (1) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति प्रबंध-बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं ।

(2) प्रत्येक कुलानुशासक दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र होगा ।

पुस्तकालय अध्यक्ष

10. (1) पुस्तकालय अध्यक्ष, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंध-बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे प्रबंध-बोर्ड द्वारा सौंपे जाएं ।

प्रबंध-बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति

11. प्रबंध-बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति प्रबंध-बोर्ड के पांच सदस्यों से होगी ।

प्रबंध-बोर्ड की शक्तियां और दृश्य

12. (1) प्रबंध-बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन करने की शक्ति होगी ।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रबंध-बोर्ड को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के प्रतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उसकी उपलब्धियां अवधारित करना, और प्राचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्राचार्यों के कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना ;

परन्तु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों के संबंध में कोई कार्रवाई, प्रबंध-बोर्ड द्वारा, विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी ;

(ii) उतने प्राचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को, जितने आवश्यक हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों को, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना ;

(iii) प्रशासनिक, अनुसन्धीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना ;

(iv) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुटी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ;

(v) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना ;

(vi) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारों नियुक्त करना जो वह ठीक समझे ;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ;

(viii) विश्वविद्यालय के धन को जिसके अन्तर्गत अनुपयोजित आय है समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना जिसमें ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है ;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधनों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना ;

(xii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों को, जो किसी कारण से, अपने को व्यक्ति अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना ;

(xiii) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसों, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् नियत करना ;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना ;

(xv) ऐसे विशेष हस्तजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक हों ;

(xvi) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति कुलपति, प्रतिकुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव या वित्त अधिकारी को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकरण को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित करना ;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार अंशित करना ;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अध्याधारण करना ;

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

योजना और विद्या समिति का गठन, उसकी शक्तियां और दृश्य

13. (1) योजना और विद्या समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिल कर बनेगी, अर्थात् :—

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उपाध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष,

(ii) कुलपति,

(iii) प्रतिकुलपति,

(iv) सभी विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष,

(v) विश्वविद्यालय के तीन शिक्षक, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएंगे,

(vi) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि,—

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान,

(ख) पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अधीन स्थापित पूर्वोत्तर परिषद्,

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, और

(घ) असम राज्य सरकार,

(vii) तीन विशिष्ट शिक्षा शास्त्री, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,

(viii) लोक जीवन में ख्यातिप्राप्त तीन व्यक्ति, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे,

(ix) कुलसचिव, जो समिति का पदेन सचिव होगा ।

(2) समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति को अपने में निहित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के विद्या और विकास कार्यक्रमों से संबंधित विषयों पर अर्थात् पाठ्यक्रमों का पता लगाने और उन्हें आरंभ करने, कैंपस संरचना का विकास करने, प्रवेश और भर्ती नीति की विरचना करने के बारे में प्रबन्ध-बोर्ड को सलाह देना,

(ख) विद्या परिषद् और योजना बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करना,

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इन परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या व्यस्त किए जाएं।

(4) योजना और विद्या सभिति का अधिवेशन ऐसे अंतरालों पर होगा जो वह समीचीन समझे किन्तु उसका अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(5) धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन कुलाध्यक्ष द्वारा अवधारित तारीख को, यह परिनियम प्रभावहीन हो जाएगा।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति

14. विद्या परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियाँ

15. अधिनियम, परिनियमों, और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् की, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थाओं में सहकारी अध्यापन, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निवेश देना;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय करना, अन्तर्विद्यापीठ आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वयन करने के लिए समितियों या बोर्डों की स्थापना करना ;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरूचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या प्रबंध-बोर्ड द्वारा निर्देशित किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना ; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययन वृत्तियों के लिए जाने, फीस रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों।

योजना बोर्ड

16. (1) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित शैक्षिक कार्यक्रमों का पुनर्विचोदन करना ;

(ख) विश्वविद्यालय में शिक्षा की संरचना करना जिससे कि छात्रों को अपने व्यक्तित्व और समाज में लाभदायक कार्य के लिए कौशल के विकास के लिए समुचित विषयों के विभिन्न संयोजन प्रस्थापित करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकें ;

(ग) मूल्योन्मुखी शिक्षा के लिए सहायक वातावरण और पर्यावरण सृजित करना ; और

(घ) नई अध्यापन-विद्या प्रक्रियाओं का विकास करना जिनमें व्याख्यान, अनुशिक्षण, संगोष्ठियाँ, निदर्शन, स्वतः अध्ययन और सामूहिक व्यावहारिक परियोजनाएं सम्मिलित होंगी।

(2) योजना बोर्ड को विश्वविद्यालय के विकास के संबंध में सलाह देने और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी जिससे कि वह अभिनिर्देश किया जा सके कि क्या वे उन आधारों पर हैं, जिनके संबंध में उसने सिफारिश की है तथा उसे उससे संबंधित किसी विषय पर प्रबन्ध-बोर्ड और विद्या-परिषद् को सलाह देने की शक्ति भी होगी।

(3) विद्या परिषद् और प्रबन्ध-बोर्ड योजना बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिए आवद्ध होंगे और ऐसी सिफारिशों को, जो उनके द्वारा स्वीकार की जाएं, कार्यान्वित करेंगे।

(4) योजना बोर्ड की ऐसी सिफारिशों को, जिन्हें प्रबन्ध-बोर्ड या विद्या परिषद् द्वारा खंड (3) के अधीन स्वीकार नहीं किया गया है, प्रबन्ध-बोर्ड या विद्या परिषद् को सिफारिशों के साथ कुलपति द्वारा कुलाध्यक्ष को सलाह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और कुलाध्यक्ष की सलाह, यथास्थिति, प्रबन्ध-बोर्ड या विद्या परिषद् द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

(5) योजना बोर्ड उसनी समितियां गठित कर सकेगा, जितनी विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको मानीटर करने के लिए आवश्यक हों।

विद्यापीठ और विभाग

17. (1) विश्वविद्यालय में उतने विद्यापीठ होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा। प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा उसमें समनुदेशित किए जाएं।

(ख) किसी विभाग की स्थापना या समाप्ति परिनियमों द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

परन्तु योजना और विद्या समिति या विद्या परिषद् की सिफारिश पर प्रबन्ध-बोर्ड, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा जिसमें विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक लगाए जाएंगे, जिन्हें प्रबन्ध-बोर्ड आवश्यक समझे।

(ग) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —

(i) विभाग के शिक्षक,

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति,

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष,

(iv) विभाग में संलग्न मानद् आचार्य, यदि कोई हो, तथा

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

अध्ययन बोर्ड

18. (1) प्रत्येक विभाग में एक स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड और एक स्नातक पूर्व अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा सम्बन्ध विद्यापीठ बोर्ड की ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित विषयों के बारे में सकारण करना होगा—

(क) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षाओं की नियुक्ति ;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परन्तु स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

(4) स्नातक पूर्व अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके कृत्य और उसके सदस्यों की पदावधि, अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

वित्त समिति

19. (1) वित्त समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति ;

(ii) प्रतिकुलपति ;

(iii) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक प्रबन्ध-बोर्ड का सदस्य होगा ; तथा

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति, वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है, तो उसे वित्तसमिति टिप्पण लिखने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन वर्ष में कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन पदों की जो बजट में शामिल नहीं की गई है, प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जानी चाहिए।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार और टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् प्रबन्ध-बोर्ड के अनुमोदन के लिए पेश किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष में कुल आयर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी, जो विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिनके अन्तर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में उधारों के प्रागम की हो सकेंगे) ।

चयन समितियाँ

20. (1) प्राचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्रबन्ध-बोर्ड को सिफारिश करने के लिए चयन समितियाँ होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्दिशिता तथा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

सारणी

(1)	(2)
प्राचार्य	(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष, यदि वह, प्राचार्य हो । (ii) एक प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा । (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, प्रबंध-बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या-परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे प्राचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या उसमें उनकी रुचि के कारण की गई हो ।
उपाचार्य/ प्राध्यापक	(i) संबंधित विभाग का अध्यक्ष । (ii) एक प्राचार्य जो कुलपति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा । (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, प्रबंध-बोर्ड द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनकी सिफारिश विद्या-परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या उसमें उनकी रुचि के कारण की गई हो ।
कुल सचिव, वित्त अधिकारी	(i) प्रबंध-बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित उसके दो सदस्य । (ii) प्रबंध-बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।
पुस्तकालय अध्यक्ष	(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/

(1)

(2)

पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो और जो प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो और प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।

विश्वविद्यालय द्वारा जलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य

तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, और जिनमें से दो प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा और एक विद्या-परिषद् द्वारा उनके ऐसे विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महा-विद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1—जब नियुक्ति अन्तर विषयक परियोजना के लिए भी जानी हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष सम्मिलित जाएगा।

टिप्पण 2—नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्राचार्य उस विशिष्ट विषय से संबंधित प्राचार्य होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी प्राचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु चयन समिति के अधिवेशन, कुलाध्यक्ष के नामनिर्दिष्टि के और खण्ड (2) के अधीन प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी जब तक:—

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्दिष्टि और प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें, और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्दिष्टि और प्रबन्ध-बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें।

(4) किसी चयन समिति का अधिवेशन कुलपति द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिकुलपति द्वारा बुलाया जाएगा।

(5) सिफारिश करने में चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकृत की जाएगी।

(6) यदि प्रबन्ध-बोर्ड, चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगा और मामले को अन्तिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगा।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियों नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति को भरना आवश्यक है तो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अधिक अवधि के लिए नियुक्ति की जा सकेगी ।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबंधित विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशनी होगा :

परन्तु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशनी हों सकेंगे :

परन्तु यह और कि मृत्यु या अन्य किसी कारण से कारित अध्यापन पदों की अचानक आकस्मिक रिक्तियों की दशा में, संकायाध्यक्ष, संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा ;

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि उसका, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में चयन नहीं कर लिया जाता ।

नियुक्ति का विशेष ढंग

21. (1) परिनियम 20 में किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध-बोर्ड, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, प्राचार्य या उपाचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद, स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगा ।

(2) प्रबंध-बोर्ड, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा ।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति

22. प्रबंध-बोर्ड परिनियम 20 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

मान्यताप्राप्त शिक्षक

23. (1) मान्यता प्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति से किए जाएंगे जैसी अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

(3) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए अधिकृत रीति में गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना कोई शिक्षक मान्यताप्राप्त शिक्षक नहीं होगा।

(4) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक से मान्यता वापस ले सकेगी।

परन्तु ऐसा कोई संकल्प पारित तभी किया जाएगा जब उस व्यक्ति को, ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दशित करने की लिखित सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साध्य पर, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, विद्या परिषद् द्वारा विचार कर लिया जाता है।

(6) खण्ड (5) के अधीन मान्यता वापस लेने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसकी सूचना की तारीख से तीन मास के भीतर, प्रबन्ध-बोर्ड को अपील कर सकेगा, जो उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

समितियाँ

24. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण, उसकी स्थायी या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) खण्ड (1) के अधीन नियुक्त कोई ऐसी समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा बाद में पुष्टि की जाने के अधीन होगी।

शिक्षकों आदि के सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता

25. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) खण्ड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास जमा कराई जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता

26. विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता से शासित होंगे।

ज्येष्ठता सूची

27. (1) जब कभी परिनिर्णयों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार अक्रान्तक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवा काव और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार, जो प्रबंध-बोर्ड समय-समय पर चिह्नित करे, किया जाएगा।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनिर्णयों के उपबंध लागू होंगे उनके प्रत्येक वर्ग की साबित एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी ग्रेड विशेष में लगातार सेवा-काल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों का सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुल सचिव स्वप्रेरणा से यह मामला प्रबंध-बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुगोच करता है तो वह मामला प्रबंध-बोर्ड को प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर निर्णायक अन्तिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना

28. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन है वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए मध्यम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलम्बित कर सकेगा और प्रबंध-बोर्ड को उन परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट करेगा, जिनमें वह आदेश किया गया था।

परन्तु, यदि प्रबंध-बोर्ड को यह राय है कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य का निलम्बन नहीं होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहन कर सकेगा।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की सविदा के विवरणों में या सेवा के अन्य विवरणों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के संबंध में प्रबंध-बोर्ड और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक को या शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य का अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) उपर्युक्त के विजाय, यथास्थिति, प्रबंध-बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए हकदार तभी होगा जब उसके लिए उचित कारण हों, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो, या सूचना के बदले तीन मास के केवल वेतन का भंडाव किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी भी शिक्षक शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को उसके हटाए जाने का आदेश किया गया है।

परन्तु जहां शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलम्बित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख को वह निलम्बित किया गया था।

(6) इस परिणियम के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारित्व का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, प्रबंध-बोर्ड, या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो, यथास्थिति, प्रबंध-बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, प्रबंध-बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

मानद उपाधियां

29. (1) प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा :

परन्तु आपात स्थिति की दशा में स्वरक्षण से प्रबंध-बोर्ड, ऐसी प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) प्रबंध-बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई मानद उपाधि वापस ले सकेगा ।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना

30. प्रबंध-बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई संकल्प पारित तभी किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, वह हेतुक दशित करने की लिखित सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब प्रबंध-बोर्ड उसके आक्षेपों पर यदि कोई हों, और किसी माध्यम पर, जो वह उनके समर्थन में पेश करे, विचार कर लिया जाता है ।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना

31. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्यवाई संबंधी सभी शक्तियां, कुलपति में निहित होंगी ।

(2) कुलपति अपनी सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की उपाय ऐसी कार्यवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी शक्तियों के प्रयोग में, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किसी छात्रों को किसी निर्विष्ट अवधि के लिए निलंबित या निलंबित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी

महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश नताई गई अवधि तक न दिया जाए अथवा उसे उतने जुमाने का बण्ड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने में एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का जिसमें वह या वे सम्मिलित हुए हों, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों संस्थाओं, विद्यापीठों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति, प्राचार्यों और खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे, जो वे पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

दीक्षांत समारोह

32. उपाधियां प्रदान करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति में आयोजित किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष

33. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसी समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबन्ध नहा किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबन्ध किया गया है वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र

34. प्रबन्ध-बोर्ड, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, कुल-सचिव को संबोधित पत्र द्वारा त्याग सकेगा और ऐसा त्याग पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हताएं

35. (1) कोई भी व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य खुद जाने और होने के लिए निरर्हत होगा, यदि—

(i) वह विकृत-चित्त है;

(ii) वह अनुमोचित दिवालिया है;

(iii) वह ऐसे किसी अपराध के तहत, जिससे नैतिक अधमता अनर्बलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास में अप्रयुक्त अवधि के कारावास से वंचित किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित निरक्षरताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो, मामूली तौर पर भारत में निवासी न हो विश्वविद्यालय का अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।

अन्ध निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकरणों की सदस्यता

37. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होने के नाते या किसी विशिष्ट नियुक्ति पर होने के नाते विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक ऐसा पद धारण करेगा या सदस्य बना रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशिष्ट नियुक्ति पर बना रहता है।

पूर्व छात्र संगम

38. (1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिप्राय, अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई सदस्य, मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख के पहले कम से कम एक वर्ष तक संगम का सदस्य रहा है, और विश्वविद्यालय का कम से कम पांच वर्ष की अवस्थिति का स्नातक है।

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद्

39. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जो निम्नलिखित में मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा ;

(ii) वे सभी छात्र, जिन्होंने पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के दौरान अध्ययन, ललित कला, क्रीडा और विस्तार कार्य के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त किए हैं ;

(iii) बीस छात्र, जो अध्ययन, क्रीडा क्रियाकलापों और व्यक्तित्व के सर्वोत्तोन्मुखी विकास में प्रतिभा के आधार पर विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ;

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को विश्वविद्यालय से संबंधित कोई विषय छात्र परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा, यदि अध्यक्ष ऐसा अनुज्ञात

करे और उसे ऐसे किसी भी अधिवेशन में चर्चा में भाग लेने का उस समय अधिकार होगा जब उस विषय के बारे में विचार किया जाए।

(2) अध्ययन, छात्र कल्याण कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के माध्यम से संबन्धित महत्व के अन्य विषयों के बारे में विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों को सुझाव देना छात्र परिषद् के कर्तव्य होंगे और ऐसे सुझाव सर्वसम्मति के आधार पर दिए जाएंगे।

(3) छात्र परिषद्, शैक्षणिक वर्ष में कम से कम एक बार, अधिमानतः उस वर्ष के प्रारंभ में, अपना अधिवेशन करेगी।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे

40. (1) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, प्रबंध-बोर्ड द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति में किसी समय भी संशोधित, निर्गमित या पश्चिन्नित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 28 में प्रणयित ऐसे मामलों के बारे में, जो उस धारा की उपधारा (1) के खंड (द) में प्रणयित मामलों में मित्त हैं, प्रबंध-बोर्ड द्वारा कोई अध्यादेश, तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्राप्ति विद्या परिषद् द्वारा पस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) प्रबंध-बोर्ड को हम बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन पस्थापित किसी अध्यादेश के प्राप्ति का संशोधन करे किन्तु वह पस्थापना को नामंजूर कर सकेगा या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्राप्ति का या उसके किसी भाग का उन किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव प्रबंध-बोर्ड करे, उसे वापस भेज सकेगा।

(4) जहां प्रबंध-बोर्ड ने विद्या परिषद् द्वारा पस्थापित किसी अध्यादेश के प्राप्ति को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद्, उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब सून प्राप्ति उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक के बहुमत में पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है, तब प्राप्ति प्रबंध-बोर्ड को वापस भेजा जा सकेगा, जो या तो उसे मान लेगा या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगा, जिसका विनिश्चय परिलक्ष्य होगा।

(5) प्रबंध-बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(6) प्रबंध-बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, उसके श्रंगिकार किए जाने की तारीख, से दो सप्ताह के भीतर, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि वह किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और कुलाध्यक्ष, पस्थापित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में प्रबंध-बोर्ड को, यथा संभव शीघ्र सूचना करेगा। विश्वविद्यालय ने विपणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुलाध्यक्ष अध्यादेश को निलम्बित करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विनियम

41. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, पश्चिनियमों और अध्यादेशों में सुसंगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् —

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करना और गणपूर्ति के लिए अर्पित सदस्यों की संख्या नियत करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा, विनियमों द्वारा, विहित किए जाने अपेक्षित हैं,

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों का उपबन्ध करना, जो मुख्यतः ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों के बारे में होंगे और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, उस प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने के लिए और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए, विनियम बनाएगा ।

(3) प्रबन्ध-बोर्ड, इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या ऐसे किसी विनियम के रद्द किए जाने का निर्देश दे सकेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

42. अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्व-विद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी कोई शक्ति, अपने नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग का संपूर्ण दायित्व ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित रहेगा ।

उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 50)

[27 अगस्त, 1993]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चवासीमवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 18 जून, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1986 का 88

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 की उपधारा (1) में,—

धारा 2 का संशोधन।

(1) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(क) “समुचित प्रयोगशाला” से ऐसी कोई प्रयोगशाला या संगठन अभिप्रेत है जो—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(ii) किसी राज्य सरकार द्वारा, उसे भारगवर्णक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विहित किए जाए, मान्यताप्राप्त है; या

(iii) कोई ऐसी प्रयोगशाला या संगठन है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है, जिसका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा, किसी माल का यह अवधारण करने की दृष्टि से कि क्या उस माल में कोई त्रुटि है, विश्लेषण या परीक्षण करने के लिए अनुरक्षण, वित्तपोषण किया जाता है या सहायता की जाती है ;’

(2) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(कक) “शाखा कार्यालय” से अभिप्रेत है—

(i) कोई ऐसा स्थापन जो विरोधी पक्षकार द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किया गया है; या

(ii) कोई ऐसा स्थापन जो वही क्रियाकलाप या सारतः वही क्रियाकलाप कर रहा है जो स्थापन के मुख्य कार्यालय द्वारा किया जाता है, ;

(3) खण्ड (ख) के उपखण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) जहां एक ही हित रखने वाले अनेक उपभोक्ता हैं वहां एक या अधिक उपभोक्ता ।” ;

(4) खण्ड (ग) में,—

(अ) उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(i) किसी व्यापारी द्वारा कोई अनुचित व्यापारिक व्यवहार या कोई अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अपनाया गया है ;” ;

(आ) उपखंड (ii) में, “परिवाद में उल्लिखित माल” शब्दों के स्थान पर, “उसके द्वारा क्रय किए गए या उसके द्वारा क्रय किए जाने के लिए करार किए गए माल” शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) उपखंड (iii) में, “परिवाद में वर्णित सेवाओं” शब्दों के स्थान पर, “उसके द्वारा भाड़े पर ली गई या उपभोग की गई अथवा भाड़े पर लिए जाने या उपभोग किए जाने के लिए करार की गई सेवाओं” शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(v) ऐसा माल, जो उपभोग किए जाने पर जीवन और सुरक्षा के लिए परिसंकटमय होगा, तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के उल्लंघन में, जो उस माल की अंतर्वस्तु, रीति और उपभोग के प्रभाव की वास्तव सूचना संप्रदर्शित करने की व्यापारी से अपेक्षा करती है, जनता को विज्ञापन के लिए प्रस्थापित किया गया है ;” ;

(5) खण्ड (घ) में,—

(अ) उपखंड (ii) में “भाड़े पर लेता है” शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, “भाड़े पर लेता है या उनका उपभोग करता है” शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्पष्टीकरण—उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए, “वाणिज्यिक प्रयोजन” के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा ऐसे माल का उपभोग नहीं है जिसका उसने स्वनियोजन द्वारा अपनी जीविका उपार्जन के प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से क्रय और उपभोग किया है ; ;

(6) खण्ड (ब) में, “किसी विधि द्वारा या उसके अधीन” शब्दों के पश्चात् “अथवा किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन” शब्द रखे जाएंगे ;

(7) खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(अअ) “सदस्य” के अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग या जिला पीठ का अध्यक्ष और कोई सदस्य है;” ;

(8) खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(बब) “अवरोधक व्यापारिक व्यवहार” से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जो किसी उपभोक्ता से, यथास्थिति, किसी माल या सेवा का क्रय करने, उसे भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने की, किसी अन्य माल या सेवा का क्रय करने, उसे भाड़े पर लेने या उसका उपभोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के रूप में, अपेक्षा करता है;” ;

(9) खण्ड (ण) में, “बोर्ड या निवास अथवा दोनों” शब्दों के पश्चात्, “गृह निर्माण,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(10) खण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(द) “अनुचित व्यापारिक व्यवहार” से ऐसा व्यापारिक व्यवहार अभिप्रेत है जिसमें किसी माल के विक्रय, उपयोग या प्रदाय के संप्रवर्तन के प्रयोजन के लिए अथवा कोई सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए, कोई अनुचित पद्धति अथवा अनुचित या प्रबंचक व्यवहार जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कोई व्यवहार है, अपनाया जाता है, अर्थात् :—

(1) मौखिक रूप से या लिखित रूप में या दृश्यरूपण द्वारा कोई ऐसा कथन करने का व्यवहार जिसमें,—

(i) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि माल किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी, मात्रा, श्रेणी, संरचना, अक्षिमान या माडल का है ;

(ii) यह मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है कि सेवाएं किसी विशिष्ट स्तरमान, क्वालिटी या श्रेणी की हैं ;

(iii) किसी पुनर्निर्मित, बरते हुए, नवीकृत, दुरुस्त किए गए या पुराने माल के नया माल होने का मिथ्या व्यपदेशन किया जाता है ;

(iv) यह व्यपदेशन किया जाता है कि माल या सेवाओं को ऐसा प्रायोजन, अनुमोदन, कार्यकरण, लक्षण, उपसाधन, प्रयोग या फायदे प्राप्त हैं जो ऐसे माल या सेवाओं के नहीं हैं ;

(v) यह व्यपदेशन किया जाता है कि विक्रेता या प्रदायकर्ता को ऐसा प्रायोजन या अनुमोदन या सहबद्धता प्राप्त है जो ऐसे विक्रेता या प्रदायकर्ता को प्राप्त नहीं है ;

(vi) किसी माल या सेवाओं की आवश्यकता या उपयोगिता से संबंधित कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन किया जाता है ;

(vii) जनता को किसी उत्पाद के या किसी माल के निष्पादन, प्रभावकारिता या अस्तित्व की दीर्घता की, जो उसके पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित नहीं है, कोई वारंटी या प्रत्याभूति दी जाती है ;

परंतु जहां इस आशय की प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी वारंटी या प्रत्याभूति पर्याप्त या समुचित परीक्षण पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के समूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा करता है ;

(viii) जनता को इस रूप में व्यपदेशन किया जाता है जो—

(i) किसी उत्पाद या किसी माल या सेवाओं की वारंटी या प्रत्याभूति, या

(ii) किसी वस्तु या उसके किसी भाग को बदलने, उसके अनुरक्षण या उसकी मरम्मत करने अथवा कोई सेवा, जब तक कि उससे कोई विनिर्दिष्ट परिणाम प्राप्त न हो जाए, पुनः करने या उसे जारी रखने का वचन,

देने के लिए तात्पर्यित है, यदि ऐसी तात्पर्यित वारंटी या प्रत्याभूति या वचन तात्त्विक रूप से भ्रामक है अथवा यदि इस बात की कोई व्यक्तिगुक्त संभावना नहीं है कि ऐसी वारंटी, प्रत्याभूति या वचन का पालन किया जाएगा ;

(ix) उस कीमत के बारे में जनता को तात्त्विक रूप से भ्रुलावा दिया जाता है जिस पर किसी उत्पाद या वैसे ही उत्पाद या माल या सेवा का मामूली तौर पर विक्रय किया जाता है अथवा वह उपलब्ध कराई जाती है, तथा इस प्रयोजन के लिए कीमत के बारे में किसी व्यपदेशन को उस कीमत के प्रति निर्देश करने वाला समझा जाएगा जिस पर सुसंगत बाजार में साधारणतया वह उत्पाद या माल विक्रेताओं द्वारा विक्रय किया गया है, या सेवाएं प्रदायकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जब तक कि यह स्पष्टतया विनिर्दिष्ट न किया गया हो कि यह वह कीमत है, जिस पर, उस व्यक्ति द्वारा, वह उत्पाद विक्रय किया गया है, या सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से व्यपदेशन किया गया है ;

(x) ऐसे मिथ्या या भ्रामक तथ्य दिए जाते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के माल, सेवाओं या व्यापार का अपकथन करते हैं ।

स्पष्टीकरण—खंड (1) के प्रयोजनों के लिए,
ऐसे कथन के बारे में जो—

(क) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु पर या उसके गैर या आधान पर अभिव्यक्त है ; या

(ख) विक्रय के लिए प्रस्थापित या संप्रदर्शित किसी वस्तु से संलग्न, उसमें रखी हुई या उसके साथ की किसी चीज पर या किसी ऐसी चीज पर, जिस पर वह वस्तु संप्रदर्शन या विक्रय के लिए मड़ी हुई है, अभिव्यक्त है ; या

(ग) किसी ऐसी वस्तु में या उस पर अंतर्विष्ट है जो जनता को विक्रय की जाती है, भेजी जाती है परिदान की जाती है, पारेषित की जाती है या किसी भी अन्य रीति से उपलब्ध कराई जाती है ;

यह समझा जाएगा कि वह ऐसा कथन है जो जनता को उस व्यक्ति द्वारा और केवल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसने उस कथन को इस प्रकार अभिव्यक्त, कराया था या अंतर्विष्ट कराया था ;

(2) ऐसे माल या सेवाओं के किसी रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए, जो उस रियायती कीमत पर विक्रय या प्रदाय के लिए प्रस्थापित की जाने के लिए आशयित नहीं है, या ऐसी अवधि के लिए जो, और ऐसी मात्रा में जो, उस बाजार के स्वरूप को, जिसमें कारबार किया जाता है, कारबार के स्वरूप और आकार को तथा विज्ञापन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त है, किसी समाचारपत्र में या अन्यथा किसी विज्ञापन के प्रकाशन की अनुज्ञा देता है ।

स्पष्टीकरण—खंड (2) के प्रयोजन के लिए, “रियायती कीमत” से—

(क) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो किसी विज्ञापन में, मामूली कीमत के प्रति निर्देश से या अन्यथा रियायती कीमत कथित की गई है ; या

(ख) ऐसी कीमत अभिप्रेत है जो ऐसा व्यक्ति, जो उस विज्ञापन को पढ़ता, सुनता या देखता है, उन कीमतों को ध्यान में रखते हुए जिन पर विज्ञापित उत्पाद या वैसे ही उत्पाद मामूली तौर पर विक्रय किए जाते हैं, युक्तियुक्त रूप से रियायती कीमत समझेगा ;

(3) (क) दान, इनामों या अन्य वस्तुओं को प्रस्थापित किए जाने की अनुज्ञा देता है किंतु जिन्हें प्रस्थापित किए गए रूप में दिए जाने का कोई आशय नहीं होता है अथवा जिनसे यह धारणा उत्पन्न होती है कि कोई चीज मुफ्त दी जा रही है या प्रस्थापित की जा रही है, जबकि उसकी कीमत पूर्णतः या भागतः उस रकम में आ जाती है जो उस संपूर्ण संव्यवहार में प्रसारित की जाती है ;

(ख) किसी उत्पाद के विक्रय, उपयोग या प्रदाय का अथवा किसी कारखानी हित का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः

संप्रवर्तन करने के प्रयोजन के लिए, किसी प्रतियोगिता, लाटरी, संयोग-प्रधान या कौशल-प्रधान खेल के संचालन की अनुज्ञा देता है ;

(4) ऐसे माल के विक्रय या प्रदाय की, जो उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए आशयित है या इस किस्म का है जिसका उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाना संभाव्य है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए अनुज्ञा देता है कि वह माल निष्पादन, संरचना, अंतर्वस्तु, डिजाइन, सश्रिमाण, परिरूप या पैक करने के संबंध में, जो माल का उपयोग करने वाले व्यक्ति को क्षति की जोखिम का, निवारण करने या उसे कम करने के लिए आवश्यक है, उन स्तरमानों के अनुरूप नहीं है जो मध्यम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए हैं ;

(5) माल की जमाखोरी या उसका नाश किए जाने की अनुज्ञा देता है या माल के विक्रय किए जाने अथवा विक्रय के लिए उसके उपलब्ध कराए जाने या कोई सेवा उपलब्ध कराए जाने से इंकार करता है, यदि ऐसी जमाखोरी या ऐसा नाश या इंकार उसका या अन्य समरूप माल या सेवाओं का वाम बढ़ाता है या बढ़ाने की प्रवृत्ति रखता है या वह बढ़ाने के लिए आशयित है ।'।

धारा 4 का
संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग" शब्दों के स्थान पर, "उपभोक्ता कार्यकलापों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का
संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में, "के कम से कम तीन अधिवेशन किए जाएंगे" शब्दों के स्थान पर, "का कम से कम एक अधिवेशन किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का
संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,—

(i) खंड (क) में, "माल" शब्द के पश्चात्, "और सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "यथास्थिति, माल या सेवाओं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) में, "माल" शब्द के पश्चात् "और सेवाएं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (ङ) में, "अनुचित व्यापारिक व्यवहार" शब्दों के पश्चात् "या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 7 का
संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों का भारसाधक मंत्री, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उतने अन्य सरकारी या गैर सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) राज्य परिषद् का अधिवेशन आवश्यकानुसार होगा किन्तु प्रत्येक कम से कम दो अधिवेशन किए जाएंगे ।

(4) राज्य परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे और वह अपने कारबार के संव्यवहार के बारे में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।” ।

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

धारा 9 का संशोधन ।

(1) खण्ड (क) में,—

(i) “केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यदि राज्य सरकार ठीक समझती है तो वह किसी जिले में एक से अधिक जिला पीठों की स्थापना कर सकेगी ।” ।

(2) खण्ड (ख) में से “केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन ।

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक जिला पीठ निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश है, या रह चुका है या होने के लिए अर्हित है, उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) दो अन्य सदस्य, जो योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक कार्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या उनसे संबंधित समस्याओं के संबंध में कार्यवाही करने की योग्यता हो और उनमें से एक महिला होगी ।” ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(1क) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष —अध्यक्ष

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव — सदस्य

(iii) राज्य में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव —सदस्य” ।

9. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

धारा 11 का संशोधन ।

(1) उपधारा (1) में, “एक लाख रुपए से कम है” शब्दों के स्थान पर “पाच लाख रुपए से अधिक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे ;

(2) उपधारा (2) में,—

(i) खण्ड (क) में, “कारबार करता है या” शब्दों के स्थान पर “कारबार करता है या उसका शाखा कार्यालय है या वह” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खण्ड (ख) में,—

(अ) “कारबार करता है” शब्दों के स्थान पर, “कारबार करता है या उसका शाखा कार्यालय है या वह” शब्द रखे जाएंगे;

(घा) “कारबार नहीं करते” शब्दों के स्थान पर “कारबार नहीं करते या शाखा कार्यालय नहीं रखते” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा 10. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
का प्रतिस्थापन।

रीति, जिससे
परिवाद किया
जाएगा।

‘12. विक्रीत या परिदत्त या विक्रय या परिदान किए जाने के लिए करार किए गए किसी माल अथवा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने के लिए करार की गई किसी सेवा के संबंध में कोई परिवान निम्न-लिखित द्वारा जिलापीठ को किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह उपभोक्ता जिसको ऐसा माल विक्रीत या परिदत्त किया जाता है या जिससे विक्रय या परिदान किए जाने के लिए करार किया जाता है अथवा जिसको ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं या जिससे ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवाए जाने के लिए करार किया जाता है;

(ख) कोई मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम चाहे वह उपभोक्ता, जिसको उस माल का विक्रय या परिदान किया जाता है या जिससे विक्रय या परिदान किए जाने का करार किया जाता है अथवा जिसको ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, या जिससे ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए करार किया जाता है, ऐसे संगम का सदस्य हो या नहीं;

(ग) जहां एक ही हित रखने वाले बहुत से उपभोक्ता हैं वहां इस प्रकार हितबद्ध सभी उपभोक्ताओं की ओर से या उनके फायदे के लिए जिलापीठ की अनुज्ञा से एक या अधिक उपभोक्ता;

(घ) केन्द्रीय या राज्य सरकार।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम” से कम्पनी अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम अभिप्रेत है।’

1956 का 1

धारा 13 का
संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्न-लिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6) जहां परिवारी धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में निर्दिष्ट कोई उपभोक्ता है वहां सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश 1 के नियम 8 के उपबंध इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उसमें वाद या छित्री के प्रति प्रत्येक निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी परिवार या उस पर जिलापीठ के आदेश के प्रति निर्देश है।”

1908 का 5

धारा 14 का
संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में,—

(i) * * * * *

(ii) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(इ) प्रश्नगत सेवाओं की दृष्टियों या कमियों को दूर करना;

(ज) अनुचित व्यापारिक व्यवहार या अवरोधक व्यापारिक व्यवहार को बन्द करना या उसे न दोहराना;

(छ) परिसंकटमय माल के विक्रय के लिए प्रस्थापना न करना;

(ज) परिसंकटमय माल की विपणन के लिए प्रस्थापित कि ए जाने से प्रत्याहृत करना ;

(झ) पक्षकारों के लिए पर्याप्त खर्चों की व्यवस्था करना ।” ।

13. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में,—

धारा 16 का संशोधन ।

(i) खंड (क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं” ;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् आने वाले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस खंड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) राज्य आयोग का अध्यक्ष —अध्यक्ष

(ii) राज्य के विधि विभाग का सचिव —सदस्य

(iii) राज्य में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का भारसाधक सचिव —सदस्य ।” ;

(iii) उपधारा (2) में, से “(जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है)” कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iv) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक या सड़सठ वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुननियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसा पद अपनी पदावधि के पूरा होने तक धारण करता रहेगा ।” ।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 के खंड (क) के उपखंड (1) में, “एक लाख रुपए से अधिक है किन्तु बस लाख रुपए से अधिक नहीं है” शब्दों के स्थान पर, “पांच लाख रुपए से अधिक है किन्तु बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 18 में, “धारा 12, धारा 13 और धारा 14 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जिलापीठ द्वारा परिवारों के निपटारे के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया” शब्द और अंकों के स्थान पर, “जिलापीठ द्वारा परिवारों के निपटारे के लिए धारा 12, धारा 13 और धारा 14 तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध” शब्द और अंक तथा “लागू होगी” शब्दों के स्थान पर “लागू होंगे” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

धारा 20 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस खंड के अधीन कोई नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं” ;

(आ) खंड (ख) के पश्चात् आने वाले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस खंड के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा अयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा —अध्यक्ष;

(ख) भारत सरकार के विधि कार्य विभाग का सचिव —सदस्य;

(ग) भारत सरकार में उपभोक्ता कार्यकलापों के बारे में कार्यवाही करने वाले विभाग का सचिव—सदस्य।”;

(ii) उपधारा (2) में से “(जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है)” कोष्ठक और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(3) राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारम्भ के पूर्व अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसा पद अपनी पदावधि के पूरा होने तक धारण करता रहेगा।”

आता 21 का संशोधन । 17. मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड (क) के उपखंड (i) में, “एक लाख रुपए” शब्दों के स्थान पर “बीस लाख रुपए” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन । 18. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“22. राष्ट्रीय आयोग को अपने समक्ष किसी परिवाद या कार्यवाही के निपटाने में,—

(क) धारा 13 की उपधारा (4), उपधारा (5) और उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी ;

(ख) विरोधी पक्षकार को यह निदेश देते हुए यह आदेश करने की शक्ति होगी कि वह धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (झ) में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक बातें करे,

और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।”।

नई धारा 24क और धारा 24ख का अंतःस्थापन । 19. मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“24क. (1) जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, कोई परिवाद तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको बाद-होतुक उद्भूत होता है, दो वर्ष के भीतर फाइल न किया गया हो।

राष्ट्रीय आयोग की शक्ति और उसको लागू प्रक्रिया ।

नई धारा 24क और धारा 24ख का अंतःस्थापन । परिसीमा अवधि ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई परिवार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि परिवारी, यथास्थिति, जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर परिवार काइल न करने का पर्याप्त कारण था :

परंतु ऐसा कोई परिवार तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिलापीठ ऐसे बिलम्ब के लिए माफी देने के अपने कारणों को अभिलिखित नहीं कर देता है ।

24ख. (1) राष्ट्रीय आयोग का निम्नलिखित विषयों में सभी राज्य प्रशासनिक नियंत्रण ।
आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात् :—

(i) मामलों के संस्थित किए जाने, निपटाए जाने, नबित रहने के बारे में कालिक विवरणियां मांगना ;

(ii) मामलों की सुनवाई, एक पक्षकार द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की प्रतियों की विरोधी पक्षकारों पर पूर्व तामील किसी भाषा में लिखे गए निर्णयों के अंग्रेजी अनुवाद दिए जाने, दस्तावेजों की प्रतियों के शीघ्र दिए जाने के बारे में एक सी प्रक्रिया अंगीकृत किए जाने की बाबत अनुदेश जारी करना ;

(iii) राज्य आयोगों या जिलापीठों के कार्यकरण का साधारण निरीक्षण, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों की, उनकी न्यायधिकल्प स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए बिना, सर्वोत्तम रूप से पूर्ति की जा रही है ।

(2) राज्य आयोग का उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी विषयों में अपनी अधिकारिता के भीतर सभी जिलापीठों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा ।” ।

20. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

धारा 26 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

“26. जहां, यथास्थिति, जिलापीठ, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष संस्थित किसी परिवार के बारे में यह पाया जाता है कि वह तंग या परेशान करने वाला है वहां वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, परिवार को खारिज करेगा और यह आदेश करेगा कि परिवारी विरोधी पक्षकार को दस हजार रुपये से अधिक ऐसे खर्चों का संदाय करे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।” ।

तंग या परेशान करने वाले परिवारों का खारिज किया जाना ।

21. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(क) “जिसके विरुद्ध परिवार किया गया है” शब्दों के पश्चात् “या परिवारी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

धारा 27 का संशोधन ।

(ख) “वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति” शब्दों के पश्चात् “या परिवारी” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

22. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

धारा 30 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, “इस अधिनियम की” शब्दों के पश्चात् “धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क),” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के बरन्वात् "धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ख) और उपधारा (4)," शब्द, अंक, अधर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

निरसन और
व्यावृत्ति ।

23. (1) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

1993 का
अध्यादेश संख्यांक
24

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद् (चंडीगढ़ निरसन) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 27)

[23 अप्रैल, 1994]

चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952
और पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद्
अधिनियम, 1961 का निरसन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद् (चंडीगढ़ निरसन) अधिनियम, 1994 है ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का, जहां तक उनका चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार है और वे उसकी विधि के भागरूप में प्रवर्तित हैं, इसके द्वारा निरसन किया जाता है ।

1953 के पंजाब अधिनियम 4 और 1961 के पंजाब अधिनियम का निरसन ।

1953 का पंजाब अधिनियम 4
1961 का पंजाब अधिनियम 3

3. पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) निरसन होते हुए भी, वह निरसन,—

व्यावृत्ति ।

(क) निरसित अधिनियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी बात पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(ख) निरसित अधिनियमों के अधीन अजित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा ; या

(ग) निरसित अधिनियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं डालेगा, पूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसा कोई विशेषाधिकार, समपहरण या दंड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो ।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 37)

[3 जून, 1994]

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,
1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन
और अंतरण) अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का
अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1994 है ।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए
विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

अध्याय 2

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,

1970 का संशोधन

1970 का 5

2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की
(जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है)
धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन ।

(i) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात् :—

“(चक) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए
विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;”

(ii) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया
जाएगा, अर्थात् :—

“(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और
इस अधिनियम में या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में

1949 का 10

परिभाषित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित 1956 का 1 है, वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 में है।”।

अध्याय 2 के शीर्षक के स्थान पर नए शीर्षक का प्रस्तावित ।

3. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अध्याय 2 में, “विद्यमान बैंकों के उपक्रमों का अंतरण” शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“विद्यमान बैंकों के उपक्रमों का अंतरण और तत्स्थानी नए बैंकों की शेयर पूंजी” ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये होगी जो बस-दम रुपये के एक सौ पचास करोड़ पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभाजित होगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी को, जैसा वह ठीक समझे बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी, किन्तु ऐसे बढ़ाए जाने या घटाए जाने के पश्चात् प्राधिकृत पूंजी, तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी या एक हजार पांच सौ करोड़ रुपये से कम नहीं होगी ।

(2ख) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी, समय-समय पर, —

(क) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसे बैंक द्वारा स्थापित आरक्षित निधि में से ऐसी समादत्त पूंजी में अंतरित करे ;

(ख) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी समादत्त पूंजी में अभिदाय करे ;

(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से शेयरों के लोक निगमन द्वारा ऐसी रीति से जुटाए, जो विहित की जाए किन्तु केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी ।

(2ग) किसी तत्स्थानी नए बैंक की संपूर्ण समादत्त पूंजी, उपधारा (2ख) के खण्ड (ग) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई समादत्त पूंजी को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार में निहित और उसको आवंटित हो जाएगी ।

(2घ) प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे शेयर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित नहीं हैं, निबन्ध रूप से अंतरणीय होंगे;

परन्तु भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति या कम्पनी अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन, जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, निगमित कोई कम्पनी अथवा ऐसी कम्पनी की कोई शाखा, चाहे वह भारत के बाहर निवासी हो या नहीं, किसी भी समय, तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों को अंतरण द्वारा या अन्यथा धारित या अर्जित नहीं करेगी जिससे कि ऐसा विनिधान कुल मिलाकर उस प्रतिशत से अधिक हो जाए, जो समावृत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति संगम है।

(2ब) केन्द्रीय सरकार से भिन्न तत्स्थानी नए बैंक का कोई शेयर धारक, तत्स्थानी नए बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में, मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(2च) प्रत्येक तत्स्थानी नया बैंक, शेयर धारकों का, एक या अधिक जिलों में, एक रजिस्टर (जिसे इस अधिनियम में रजिस्टर कहा गया है) अपने मुख्य कार्यालय में रखेगा और उसमें निम्नलिखित विधिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात्:—

(i) शेयर धारकों के नाम, पते और उपजीविकाएं, यदि कोई हों, तथा प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का, प्रत्येक शेयर को उसकी द्योतक संख्या द्वारा सुभिन्नतया इंगित करते हुए, विवरण;

(ii) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति धारक के रूप में उस प्रकार प्रविष्ट किया जाता है;

(iii) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं रह जाता है; और

(iv) ऐसी अन्य विधिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2छ) उपधारा (2च) में किसी बात क होते हुए भी, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह, ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, कंप्यूटर प्लायियों या डिस्कटों में, रजिस्टर रखे।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्टर की प्रति या उसमें से कोई उद्धरण जिसका तत्स्थानी नए बैंक के किसी ऐसे अधिकारी के, जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से शुद्ध प्रति होता प्रमाणित किया गया हो, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगा।”।

नई धारा 3क
का अंतःस्थापन ।

5. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

न्यास का रजिस्टर
में प्रविष्ट न किया
जाना ।

“3क. धारा 3 की उपधारा (2ब) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अभिव्यक्त, विवक्षित या भ्रान्तव्यक्त न्यास की सूचना, तत्स्थानी नए बैंक द्वारा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी या उसके द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी ।”

धारा 9 का
संशोधन ।

6. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (क) में, “किन्तु इस प्रकार कि ऐसे किसी बैंक की समावृत्त पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई किसी स्वीम के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक के प्रत्येक निदेशक बोर्ड में,—

(क) दो से अधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) एक ऐसा निदेशक होगा, जो केन्द्रीय सरकार का पदाधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

परन्तु कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “तत्स्थानी नया बैंक” पद के अन्तर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अर्थ में तत्स्थानी नया बैंक है ;

1980 का 40

(ग) एक ऐसा निदेशक होगा, जो रिजर्व बैंक का अधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, नामनिर्देशित किया जाएगा ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “रिजर्व बैंक का अधिकारी” के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी है जिसे उस बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54कक के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी संस्था में प्रतिनियुक्त किया जाता है ;

1934 का 2

(घ) दो से अधिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन, समय-समय पर, अधिसूचित लोक वित्तीय संस्थाओं और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित अन्य संस्थाओं में से नामनिर्देशित किए जाएंगे और जिनके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समावृत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हो ;

1992 का 15

1981 का 61

1956 का 1

1947 का 14

(ख) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन कर्मकार हैं, एक निदेशक होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, नाम निर्देशित किया जाएगा ;

1947 का 14

(च) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के, खण्ड (घ) के अधीन कर्मकार नहीं हैं, एक निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(छ) एक ऐसा निदेशक होगा, जो कम से कम पंद्रह वर्ष तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो, और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ज) खंड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, छह से अनधिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ; *

(झ) जहां धारा 3 की उपधारा (2ब) के खण्ड (ग) के अधीन निर्गमित पूंजी—

(i) कुल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां दो से अनधिक निदेशक होंगे ;

(ii) कुल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक है किन्तु चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां चार से अनधिक निदेशक होंगे ;

(iii) कुल समादत्त पूंजी के चालीस प्रतिशत से अधिक है वहां छह से अनधिक निदेशक होंगे,

जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे :

परंतु इस खण्ड के अधीन ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्देशित निदेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो जाएंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3क) उपधारा (3) के खण्ड (ज) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले या उस उपधारा के खण्ड (झ) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे—

(अ) जिन्हें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् :—

(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

(ii) बैंककारी,

(iii) सहकारिता,

(iv) अर्थशास्त्र,

(v) वित्त,

(vi) विधि,

(vii) लघु उद्योग,

(viii) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, रिजर्व बैंक की राय में तत्स्थानी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा ;

(भा) जो निक्षेपकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, अथवा

(इ) जो कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(3ख) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि किसी तत्स्थानी नए बैंक का उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचित कोई निदेशक, उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां वह, ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा, ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और ऐसे हटाए जाने पर, निदेशक बोर्ड, इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में उस समय तक के लिए सहयोजित कर सकेगा जब तक कि कोई निदेशक, तत्स्थानी नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा उसके आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप में निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।' ।

धारा 10 का संशोधन ।

7. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) उपधारा (7) में, “लाभों के अतिशेष को केन्द्रीय सरकार को अन्तरित कर देगा” शब्दों के स्थान पर “अपने शुद्ध लाभ में से लाभान्वित घोषित कर सकेगा और अधिशेष को, यदि कोई हो, प्रतिघृत रख सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (7क) में, “केन्द्रीय सरकार को” शब्दों के पश्चात् “और रिजर्व बैंक को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 10क का अन्तःस्थापन ।

8. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वार्षिक साधारण अधिवेशन ।

“10क. (1) ऐसे प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक का, जिसने धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन पूंजी निर्गमित की है, एक साधारण अधिवेशन (जिसे इस अधिनियम में वार्षिक साधारण अधिवेशन कहा गया है) ऐसे स्थान पर, जहां बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर आयोजित किया जाएगा, जो निदेशक बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन, उस तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति के पूर्व आयोजित किया जाएगा जिसको तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित धारा 10 की उपधारा (7क) के अधीन केन्द्रीय सरकार को या रिजर्व बैंक को, इनमें से जो भी तारीख पूर्वतर हो, भेजा जाता है ।

(2) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयर धारक पूर्ववर्ती 31 मार्च तक के तैयार किए गए तत्स्थानी नए बैंक के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा, लेखाओं के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए तत्स्थानी नए बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों की बाबत निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखाओं की बाबत संपरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के हक्दार होंगे ।” ।

धारा 19 का संशोधन ।

9. बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ख) तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों की प्रकृति, वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर धारित और अन्तरित किए जा सकेंगे तथा साधारण-तया शेयर धारकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सभी विषय ;

(खग) रजिस्टर का रखा जाना, और धारा 3 की उपधारा (2ब) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्टर में विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना, कम्प्यूटर प्लॉपियो या डिस्कटों पर रजिस्टर के रखे जाने में पालन किए जाने वाले रक्षोपाय, रजिस्टर का निरीक्षण और बंद किया जाना और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय ;

(खग) वह रीति जिसमें साधारण प्राधिवेशन बुलाए जाएंगे, वह प्रक्रिया जिसका उपमें अनुसरण किया जाएगा और वह रीति जिसमें भलाधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा ;

(खघ) शेयर धारकों के अधिवेशनों का आयोजित किया जाना और उनमें किया जाने वाला कारवार ;

(खङ) वह रीति जिसमें शेयर धारकों या अन्य व्यक्तियों पर तत्स्थानी नए बैंक की ओर से सूचनाओं की पानीत की जा सकेगी ;

(खच) वह रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अर्थों नावनिर्दिष्ट निर्देशक निवृत्त होंगे ;” ।

अध्याय 3

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)

अधिनियम, 1980 का संशोधन

1980 का 40

10. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की [जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम कहा गया है] धारा 2 में,—

धारा 2 का संशोधन ।

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घक) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(च) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित नहीं हैं किन्तु कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में है ।”।

1949 का 10

1956 का 1

11. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अध्याय 2 में, “विद्यमान बैंकों के उपक्रमों का अंतरण” शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

अध्याय 2 के शीर्षक के स्थान पर नए शीर्षक का प्रतिस्थापन ।

“विद्यमान बैंकों के उपक्रमों का अंतरण और तत्स्थानी नए बैंकों की शेयर पूंजी” ।

12. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2क) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 3 का संशोधन ।

“(2क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए होगी जो दस-दस रुपए के एक सौ पचास करोड़ पूर्णतः समान शेयरों में विभाजित होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी को, जैसा वह ठीक समझे, बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी, किन्तु ऐसे बढ़ाए जाने या घटाए जाने के पश्चात् प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी या एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए से कम नहीं होगी ।

(2ख) उपधारा (2) में, किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी, समय-समय पर:—

(क) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसे बैंक द्वारा स्थापित प्रारंभित निधि में से ऐसी समादत्त पूंजी में अन्तरित करे ;

(ख) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसी समादत्त पूंजी में अभिदाय करे ;

(ग) ऐसी रकम द्वारा बढ़ाई जा सकेगी जो तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, शेयरों के लोक निर्गमन द्वारा ऐसी रीति से जुटाए, जो विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार, सभी समयों पर, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करेगी ।

(2ग) किसी तत्स्थानी नए बैंक की संपूर्ण समादत्त पूंजी, उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा जुटाई गई समादत्त पूंजी को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार में निहित और उसको आबंटित हो जाएगी ;

(2घ) प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे शेयर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित नहीं हैं, निर्बाध रूप से अंतरणीय होंगे:

परन्तु भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति या कम्पनी अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन, जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, नियमित कोई कम्पनी या ऐसी कम्पनी या ऐसी कम्पनी की कोई शाखा, चाहे वह भारत के बाहर निवासी हो या नहीं, किसी भी समय तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों को अंतरण द्वारा या अन्यथा धारित या अर्जित नहीं करेगी जिससे कि ऐसा विनिधान कुल मिलाकर उस प्रतिशत से अधिक हो जाए, जो समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं हैं और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यक्ति संगम है ।

(2ङ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न तत्स्थानी नए बैंक का कोई शेयर धारक, तत्स्थानी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में, मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(2च) प्रत्येक तत्स्थानी नया बैंक, शेयर धारकों का एक या अधिक जिलों में एक रजिस्टर (जिसे इस अधिनियम में रजिस्टर कहा गया है) अपने मुख्य कार्यालय में रखेगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा, अर्थात् :—

(i) शेयर धारकों के नाम, पते और उपजीविकाएं, यदि कोई हों प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का, प्रत्येक शेयर को उसकी छोटक संख्या द्वारा सुभिन्नतया इंगित करते हुए, विवरण ;

(ii) वह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति शेयर धारक के रूप में इस प्रकार प्रविष्ट किया जाता है ;

(iii) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं रह जाता है ; और

(iv) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ;

(2छ) उपधारा (2च) में किसी बात के होते हुए भी, तत्स्थानी नए बैंक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, कम्प्यूटर क्लापियों या डिस्कटों में, रजिस्टर रखे ।

1872 का 1

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्टर की प्रति या उसमें से कोई उद्धरण तत्स्थानी नए बैंक के किसी ऐसे अधिकारी के, जो इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षर से शुद्ध प्रति होना प्रमाणित किया गया हो, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगा।”

13. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 3क का अन्तःस्थापन।

“3क. धारा 3 का उपधारा (2च) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अभिव्यक्त, विधिवत या आन्वयिक न्यास की सूचना तत्स्थानी नए बैंक द्वारा, रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी या उसके द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी।”

न्यास का रजिस्टर में प्रविष्ट न किया जाना।

14. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उपधारा (2) के खण्ड (क) में, किन्तु इस प्रकार कि ऐसे किसी बैंक की समादत्त पूंजी एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

धारा 9 का संशोधन

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक के प्रत्येक निदेशक बोर्ड में,—

(क) दो से अधिक पूर्णकालिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त किए जाएंगे ;

(ख) एक ऐसा निदेशक होगा, जो केन्द्रीय सरकार का पदाधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

परन्तु कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, तत्स्थानी नया बैंक” पद के अन्तर्गत बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अर्थ में तत्स्थानी नया बैंक है ;

1970 का 5

(ग) एक ऐसा निदेशक होगा, जो रिजर्व बैंक का अधिकारी हो और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक की सकारिण पर, नामनिर्देशित किया जाएगा।

1934 का 2

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, “रिजर्व बैंक का अधिकारी” के अन्तर्गत रिजर्व बैंक का ऐसा अधिकारी है, जिसे उस बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 54क के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी संस्था में प्रतिनियुक्त किया जाता है ;

1992 का 15

(घ) दो से अधिक ऐसे निदेशक होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या उस धारा की उपधारा (2) के अधीन, समय-समय पर, अधिसूचित लोक वित्तीय संस्थाओं और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निर्गमित अन्य संस्थाओं में से नामनिर्देशित किए जाएंगे और जिनके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समादत्त स्तर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हो ;

1981 का 61

1956 का 1

1947 का 14

(ङ) तत्स्थानी नए बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन कर्मकार है, एक निदेशक होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, नामनिर्देशित किया जाएगा;

1947 का 14

(च) तत्स्थानी नये बैंक के ऐसे कर्मचारियों में से जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के, खंड (घ) के अधीन कर्मकार नहीं है, एक निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नामनिर्देशित किया जाएगा;

(छ) एक ऐसा निदेशक होगा, जो कम से कम पन्द्रह वर्ष तक चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, नामनिर्देशित किया जायेगा;

(ज) खंड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए छह से अनधिक ऐसे निदेशक होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(झ) जहां धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन निर्गमित पूंजी—

(i) कुल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां दो से अधिक निदेशक होंगे;

(ii) कुल समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक है किन्तु चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं है वहां चार से अनधिक निदेशक होंगे ;

(iii) कुल समादत्त पूंजी के चालीस प्रतिशत से अधिक है वहां, छह से अनधिक निदेशक होंगे,

जो केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे ;

परन्तु इस खंड के अधीन ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के पश्चात् कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (ज) के अधीन नामनिर्देशित निदेशक उतनी ही संख्या में ऐसी रीति से निवृत्त हो जायेंगे, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए।

(3क) उपधारा 3 के खंड (ज) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले या उस उपधारा के खंड (झ) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे—

(अ) जिन्हें निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या अधिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, यर्थात्—

- (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- (ii) बैंककारी,
- (iii) सहकारिता,
- (iv) अर्थशास्त्र,
- (v) वित्त,
- (vi) विधि,

(vii) लघु उद्योग,

(viii) कोई अन्य विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, रिजर्व बैंक की राय में तत्स्थानी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा ;

(आ) जो निक्षेपकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ;
अथवा

(इ) जो कृषकों, कर्मकारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(3ख) जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि किसी तत्स्थानी नए बैंक का उपधारा (3) के खण्ड (झ) के अधीन निर्वाचित कोई निदेशक, उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है वहां वह, ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा ऐसे निवेशक को हटा सकेगा और ऐसे हटाए जाने पर, निदेशक बोर्ड, इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर, उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निवेशक के रूप में उस समय तक के लिए सहयोजित कर सकेगा जब तक कि कोई निदेशक, तत्स्थानी नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा उसके आगामी वार्षिक साधारण अधिवेशन में सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के शेयर धारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

15. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 में,—

धारा 10 का संशोधन ।

(i) उपधारा (7) में, “लाभों का अतिशेष केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर देगा” शब्दों के स्थान पर “अपने शुद्ध लाभ में से लाभान्वित कर सकेगा और अधिशेष को, यदि कोई हो, प्रतिधारित कर सकेगा” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (7क) में, “केन्द्रीय सरकार को” शब्दों के पश्चात् “और रिजर्व बैंक को” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

16. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 10क का अंतःस्थापन ।

“10क. (1) ऐसे प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक का, जिसने धारा 3 की उपधारा (2ख) के खण्ड (ग) के अधीन पूंजी निर्गमित की है, एक साधारण अधिवेशन (जिसे इस अधिनियम में वार्षिक साधारण अधिवेशन कहा गया है) ऐसे स्थान पर, जहां बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर आयोजित किया जाएगा जो निवेशक बोर्ड द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए :

वार्षिक साधारण अधिवेशन ।

परन्तु ऐसा वार्षिक साधारण अधिवेशन, उस तारीख से छह सप्ताह की समाप्ति के पूर्व आयोजित किया जाएगा जिसको तुलनपत्र, लाभ और हानि, लेखा तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित, धारा 10 की उपधारा (7क) के अधीन केन्द्रीय सरकार को या रिजर्व बैंक को, इनमें से जो भी तारीख पूर्वतर हो, भेजा जाता है ।

(2) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयरधारक, पूर्ववर्ती 31 मार्च तक के तैयार किए गए तत्स्थानी नए बैंक के तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखा, लेखाओं के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए तत्स्थानी नए बैंक के कार्यकरण और क्रियाकलापों पर निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र और लेखाओं पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करने के हकदार होंगे।”

धारा 19 का
संशोधन ।

17. बैंक (दूसरा) राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

“(खक) तत्स्थानी नए बैंक के शेयरों की प्रकृति, वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन शेयर धारित और अंतरित किए जा सकेंगे तथा साधारणतया शेयरधारकों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित सभी विषय;

(खख) रजिस्टर का रखा जाना और धारा 3 की उपधारा (2ब) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अतिरिक्त रजिस्टर में विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना, कंप्यूटर प्लायों या डिस्कटों पर रजिस्टर के रखे जाने में पालन किए जाने वाले रक्षोपाय, रजिस्टर का निरीक्षण और बंद किया जाना और उनसे संबंधित सभी अन्य विषय;

(खग) वह रीति जिससे साधारण अधिवेशन बुलाए जाएंगे, वह प्रक्रिया जिसका उसमें अनुसरण किया जाएगा और वह रीति जिससे, मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा ;

(खघ) शेयर धारकों के अधिवेशनों का आयोजित किया जाना और उनमें किया जाने वाला कारबार;

(खङ) वह रीति जिससे शेयरधारकों या अन्य व्यक्तियों पर तत्स्थानी नए बैंक की ओर से सूचनाओं की तामील की जा सकेगी ;

(खच) वह रीति जिससे धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट निदेशक निवृत्त होंगे ;”।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994

(1994 का अधिनियम संख्यांक 56)

[14 सितम्बर, 1994]

लोकहित में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार
अधिक बैशानिक, वन और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का
पारेषण सु-निश्चित करने के लिए नेशनल पावर ग्रिड का विकास
करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की
विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण
प्रणाली में उस कम्पनी के अधिकार, हक और हित का
अर्जन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया
लिमिटेड को अंतरण का तथा उनसे संबंधित
और उनके आनुवंशिक विषयों का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1994 है ।

अक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम की धारा 8 से धारा 11 और धारा 13 से धारा 16 के उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध, 1 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इस अधिनियम के, किसी उपबंध में, इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं ।

(क) "नियत दिन" से 1 अप्रैल, 1992 अभिप्रेत है ;

(ख) "सहयुक्त कर्मिक" से कम्पनी के ऐसे कर्मचारी अभिप्रेत हैं,
जो उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से सहयुक्त हैं ;

(ग) "कम्पनी" से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित और रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नेवेली-607801, साउथ अर्किट जिला तमिलनाडु में है ; 1956 का 1

(घ) "निगम" से पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 है; 1956 का 1

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) कम्पनी के संबंध में, "विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली" से मुख्य पारेषण लाइन [जिसके अन्तर्गत प्रति उच्च वोल्टता प्रत्यावर्ती द्वारा (अ० उ० बो० प्र० धा०) लाइनें और उच्च वोल्टता विष्ट द्वारा (उ० बो० वि० धा०) लाइनें हैं] और कम्पनी के स्वामित्व में के उप केन्द्र हैं;

(छ) "निहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निहित अभिप्रेत है;

(ज) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु, यथास्थिति, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 या कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो उन अधिनियमों में है। 1948 का 5
1956 का :

अध्याय 2

विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण

विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में कम्पनी के अधिकारों का अर्जन।

3. (1) नियत दिन को, कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली तथा उसकी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उनके अधिकार, हक और हित के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के आधार पर केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो गए हैं।

(2) इस प्रकार निहित होने के ठीक पश्चात्, उपधारा (1) के आधार पर केन्द्रीय सरकार में निहित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि वह निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है।

निहित होने का साधारण प्रभाव।

4. (1) विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसी प्रणाली से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा ऐसी सभी स्थावर और अंगम संपत्ति हैं, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, परियोजनाएं (चाहे पूर्ण हों या पूर्णता या योजना के किसी प्रक्रम पर हों), स्टोर, फालतू पुर्जें, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, सश्रिमाण उपस्कर, अनुपयोजित दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधार हैं तथा ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, कम्पनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे और उससे संबंधित सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और सभी अन्य दस्तावेज हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, किन्तु निम्नलिखित को इसके अन्तर्गत नहीं समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी को शोध्य नहीं ऋण;

(ख) नियत दिन को रोकड़ बाकी और बैंक अनिर्णय;

(ग) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व खाते मद्धे आय और व्यय।

स्पष्टीकरण—अंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में संबंधित अधिकारों के अन्तर्गत, जो धारा 3 की उपधारा (2) और इस उपधारा के अधीन निगम को अंतर्गत और उसमें निहित हो गए हैं, विद्युत शक्ति के पारेषण के लिए पारेषण प्रभारों के संग्रहण का अधिकार है और कम्पनी द्वारा नियत दिन को या उसके पश्चात् पारेषण प्रभारों के रूप में संग्रहीत कोई धनराशि (चाहे पृथक् दक्षित की गई हो या नहीं) कम्पनी द्वारा निगम को सौंपे होगी।

(2) जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उप-बंधित न किया गया हो, कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित सभी विवेक, बंधन, (भारत सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियों से भिन्न) प्रतिभूतियाँ, करार, मुक्त-रनामें, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और किसी भी प्रकृति की अन्य लिखित जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावी है और जिनमें कम्पनी पक्षकार है या जो उक्त कम्पनी के पक्ष में है, निगम के विरुद्ध या उसके पक्ष में जैसे ही पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी होंगी और उन्हें जैसे ही पूर्णतः और प्रभावी रूप से प्रवर्तित या कार्यान्वित किया जा सकेगा मानों कम्पनी के स्थान पर निगम इनमें पक्षकार रहा हो या मानों वे निगम के पक्ष में जारी की गई हों।

(3) यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को, ऐसी किसी संपत्ति या भास्ति के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतर्गत या उसमें निहित की गई है, कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया गया या लाया गया कोई बंध, अपील या अन्य कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकृति की हो, संबंधित थी तो उसका उस कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के अंतर्गत या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह बाद, अपील या अन्य कार्यवाही, धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निगम द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, खनाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी।

5. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतर्गत और उसमें निहित हो गई है, नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कम्पनी का प्रत्येक दायित्व, निगम का दायित्व होगा और निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि ऐसी कम्पनी के विरुद्ध:

कतिपय पूर्व दायित्वों के लिए निगम का दायी होना।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात,—

(क) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में राजस्व खाते मद्धे आय और व्यय की, जो नियत दिन को या उसके पश्चात् कम्पनी द्वारा, यथा-स्थिति, प्राप्त या उपगत किया गया है, लागू नहीं होगी,

(ख) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में पूंजी खाते मद्धे समाश्रित दायित्वों के बारे में जो किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के विनिश्चय के कारण उद्भूत हुए हों, अवकाश की बकाया को लागू नहीं होगी।

(2) जहां कम्पनी द्वारा किसी उधारदाता अभिकरण को नियत दिन को या उसके पश्चात् उधार या ब्याज या दोनों का कोई प्रतिसंदाय किया गया है वहां ऐसा प्रतिसंदाय निगम द्वारा किया गया समझा जाएगा और ऐसे प्रतिसंदाय की रकम की, पारेषण प्रभार के या कम्पनी द्वारा निगम को शोध्य किसी अन्य रकम के समायोजन पर, कम्पनी को निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

निगम का पट्टे-
दार या अभि-
धारी होना।

6. (1) जहां कम्पनी द्वारा अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के संबंध में कोई संपत्ति किसी पट्टे के अधीन या अभिवृत्ति के किसी अधिकार के अधीन धारित है वहां नियत दिन से ही निगम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी संपत्ति की बाबत, यथास्थिति, पट्टेदार या अभिधारी बन गया है मानो ऐसी संपत्ति के संबंध में वह पट्टा या अभिवृत्ति निगम को दी गई हो और तब ऐसे पट्टे या अभिवृत्ति के अधीन सभी अधिकारों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियम की धर्तरे पर और उसमें निहित हो गए हैं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी पट्टे या अभिवृत्ति की अवधि की समाप्ति पर, यदि निगम ऐसा चाहता है तो, ऐसा पट्टा या अभिवृत्ति का, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जिन पर वह पट्टा या अभिवृत्ति नियत दिन के ठीक पूर्व कम्पनी द्वारा धारित थी, नवीकरण किया जा सकेगा।

अंकाओं का दूर
किया जाना।

7. (1) अंकाओं को दूर करने के लिए यह बंधित किया जाता है कि धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के उपबंध वहां तक लागू होंगे जहां तक किसी संपत्ति का संबंध कम्पनी द्वारा बलाई जाने वाली विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित कारबार से तथा कम्पनी द्वारा अर्जित अधिकारों और शक्तियों, और उपगत श्रृणों, दायित्वों और बाध्यताओं और की गई सविदाओं, करारों और अन्य लिखतों से तथा भारत में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष उन मामलों के बारे में संबंधित विधिक कार्यवाहियों से है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि किसी संपत्ति का संबंध, नियत दिन को कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किसी कारबार से है या नहीं अथवा कम्पनी द्वारा अपने उक्त कारबार के प्रयोजन के लिए कोई अधिकार, शक्ति, श्रृण, दायित्व या बाध्यताएं अर्जित या उपगत की गई है या नहीं अथवा कोई सविदा, करार या अन्य लिखत की गई है या नहीं अथवा किसी वस्तुत्व का संबंध उन प्रयोजनों से है या नहीं तो वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जो, मामले में हितव्यक्त व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसका ऐसी रीति से विनिश्चय करेगी जो वह ठीक समझे।

रकम का संदाय।

8. (1) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार, हक और हित को धारा 3 और धारा 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, विहित रीति से, कम्पनी को ऐसी रकम का, जो 31 मार्च, 1992 को कम्पनी के संपरीक्षित लेखा विवरण में दिए गए (समाश्रित दायित्वों से भिन्न) दायित्वों की कटौती करने के पश्चात् सभी आस्तियों और संपत्तियों के बही मूल्य के बराबर हो, संदाय किया जाएगा।

(2) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित उसके अधिकार, हक और हित धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित या उसमें निहित किए जाने के लिए निगम द्वारा, विहित रीति से, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रकम का जो उपधारा (1) के अधीन उस सरकार द्वारा कम्पनी को संदाय की जाती है, संदाय किया जाएगा।

(3) किसी आस्ति, संपत्ति या दायित्व की प्रकृति अथवा उपधारा (1) के अधीन संदाय रकम के बारे में किसी विवाद की दशा में, वह विवाद

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जो वह नियुक्त करे और उस प्राधिकारी का उस मामले में विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 3

आस्तियों आदि का निगम को परिवर्तन

9. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को ऐसी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से, जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, संबंधित कोई आस्तियाँ, बहियाँ और कोई अन्य दस्तावेज हैं, उक्त आस्तियों, बहियों और दस्तावेजों का निगम को लेखा-ओखा देने के लिए दायी होगा और वह उनका परिवर्तन, निगम को अथवा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को करेगा जिन्हें निगम इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

व्यक्तियों का अपने कब्जे में की जास्तियों आदि का लेखा-ओखा देने का कर्तव्य।

(2) निगम, विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का, जो इस अधिनियम के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, कब्जा प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा।

(3) कम्पनी, निगम को अपनी विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से जो धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निगम को अंतरित और उसमें निहित हो गई है, संबंधित नियत दिन को विद्यमान अपनी सभी सम्पत्ति और आस्तियों की पूर्ण सूची ऐसी अवधि के भीतर देगी जो निगम इस निमित्त अनुज्ञात करे।

अध्याय 4

सहयुक्त कार्मिकों के बारे में व्यवस्था

10. (1) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली के निगम में विहित हो जाने पर, ऐसे सहयुक्त कार्मिक, जो 1 दिसम्बर, 1992 को या उसके ठीक पूर्व कम्पनी में नियोजित रहे हैं और पहले से ही निगम के कर्मचारी नहीं बन गए हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ से ही निगम के कर्मचारी बन जाएंगे और निगम के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर धारण करेंगे जो किसी भी रूप में उनसे कम अनुकूल नहीं है, जो उनके लिए तब अनुज्ञेय होती यदि उक्त प्रणाली ऐसे निहित न हुई होती और ऐसा सब तक करते रहेंगे जब तक कि निगम के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से सम्पन्न नहीं कर दिया जाता है या जब तक कि उनके पारिश्रमिक में और सेवा की अन्य शर्तों में निगम द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।

सहयुक्त कार्मिकों का बना रहना।

1947 का 14

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी सहयुक्त कार्मिकों की सेवाओं का निगम को अंतरण ऐसे कार्मिक को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हक्कार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई वादा किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

11. (1) जहाँ कम्पनी ने अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य-निधि या कोई अन्य निधि स्थापित की है, वहाँ सहयुक्त कार्मिकों से, जो पहले ही निगम के कर्मचारी बन गए हैं या जिनकी सेवाएँ इस अधिनियम के अधीन निगम को अंतरित हो गई हैं, संबंधित धनराशियाँ ऐसी भविष्य निधि या अन्य निधि में सहयुक्त कार्मिकों के अंतरण की तारीख को जमा धन राशियों में से निगम को अंतरित या उसमें निहित हो जाएंगी।

भविष्य-निधि और अन्य निधियाँ।

(2) ऐसी धनराशियों की बाबत, जो उपधारा (1) के अधीन निगम को अंतरित हो गई हैं, निगम द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

अधिनियम का
अध्यारोही प्रभाव ।

12. इस अधिनियम के उपबंधों इस अधिनियम से भिन्न, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायान्य अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री या आदेश में, समझे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

आस्तियों ।

13. कोई व्यक्ति, जो—

(क) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी ऐसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, निगम में सौंप विधार्जित करेगा; या

(ख) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सौंप अभिप्राप्त करेगा या उसे प्रतिधार्जित करेगा; या

(ग) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में संबंधित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है जानबूझकर विधार्जित करेगा अथवा उसे निगम को या निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा; या

(घ) कम्पनी की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, निगम को या उस निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा,

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा
अपराध ।

14. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

15. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए सद्भाव पूर्वक आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या निगम या कम्पनी के अथवा उस सरकार, निगम या कम्पनी के किसी अधिकारी के अथवा उस सरकार, निगम या कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) वह रीति जिससे धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम का संदाय किया जाना है ;

(ख) वह रीति जिससे धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी भविष्य-निधि या अन्य निधि में से की धनराशि की वास्तविक कार्रवाई की जाएगी ;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्या 6)

[25 मार्च, 1995]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में
यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन)
अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 1 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1975 का 51

2. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात्
मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 9, धारा 9क और धारा 9ख के स्थान
पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 9, धारा
9क और धारा
9ख के स्थान पर
नई धाराओं का
प्रतिस्थापन।

9. (1) जहाँ कोई देश या राज्यक्षेत्र किसी वस्तु का वहाँ विनिर्माण
या उत्पादन करने पर अथवा वहाँ से निर्यात करने पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः
कोई सहायकी संचित या प्रदत्त करता है, जिसके अन्तर्गत ऐसी वस्तु के परिवहन
पर कोई सहायकी है वहाँ भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात पर, चाहे वह
विनिर्माणकर्ता या उत्पादनकर्ता देश से सीधे या अन्यथा आयात की जाती हो
और चाहे वह वैसी ही दशा में आयात की जाती हो जिसमें वह विनिर्माणकर्ता
या उत्पादनकर्ता देश द्वारा निर्यात की जाती है अथवा विनिर्माण या उत्पादन
द्वारा या अन्यथा उसकी दशा परिवर्तित हो गई हो, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र
में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सहायकी की रकम से अनधिक प्रतिशुल्क अधिरोपित
कर सकेगी।

सहायता प्राप्त
वस्तुओं पर प्रति-
शुल्क।

पष्ठीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सहायकी" का अर्थ
अन्तर्गत में होता समझा जाएगा अत्र—

(क) निर्यात या उत्पादन करने वाले देश के राज्यक्षेत्र के भीतर
सरकार या किसी लोक निकाय द्वारा कोई वित्तीय योगदान निम्नलिखित
रूप में किया जाता है, अर्थात् :—

(i) सरकारी प्रक्रिया में, निधियों का प्रत्यक्ष अन्तरण

(जिसके अन्तर्गत अनुदान, ऋण और साधारण शेयर निवेशन है) अथवा निधियों या वायिक्तों का संभाव्य प्रत्यक्ष अन्तरण, अथवा दोनों, अन्तर्गृहीत हैं ;

(ii) सरकारो राजस्व, जो अन्यथा वेय है, छोड़ दिया गया है या संगृहीत नहीं किया गया है (जिसके अन्तर्गत राज्य वित्तीय प्रोत्साहन है) ;

(iii) सरकार, साधारण अवसंरचना से भिन्न, माल का सेवाएं प्रदान करती है या माल प्रय करती है ;

(iv) सरकार, निधि उपलब्ध कराने वाले किसी तंत्र को संचालित करती है, या उपरोक्त उपखंड (i) से खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रकार के कृत्यों को करने के लिए किसी प्राइवेट निकाय को सौंपती है या निर्दिष्ट करती है जो सामान्यतया सरकार में निहित होता है और ऐसी प्रक्रिया सही अर्थों में उन प्रक्रियाओं से भिन्न नहीं है जिनका सरकारों द्वारा सामान्यतया पालन किया जाता है ; या

(ख) सरकार, आय का किसी रूप में अनुदान करती है या कीमत समर्थन बनाए रखती है, जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभाव उसके राज्यक्षेत्र से किसी वस्तु के निर्यात में वृद्धि करने का या उसमें किसी वस्तु के आयात में कमी करने का होता है,

और तद्वारा कोई फायदा दिया जाता है।

(2) केंद्रीय सरकार, इस धारा के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, सहायकी की रकम का अवधारण किए जाने तक, इस उपधारा के अधीन ऐसा प्रतिशुल्क अधिरोपित कर सकेगी जो ऐसी सहायकी की रकम से अधिक नहीं होगा जिसे उसके द्वारा अनंतिम रूप से प्राक्कलित किया गया है और यदि ऐसा प्रतिशुल्क इस प्रकार अवधारित सहायकी से अधिक हो जाता है तो—

(क) केंद्रीय सरकार, ऐसे अवधारण को ध्यान में रखते हुए और ऐसे अवधारण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे प्रतिशुल्क को कम करेगी ; और

(ख) ऐसे प्रतिशुल्क के उतने भाग का प्रतिदाय किया जाएगा जो इस प्रकार कम किए गए प्रतिशुल्क के आधिक्य में संगृहीत किया गया है।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए किसी नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रतिशुल्क तब तक उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अवधारित नहीं कर दिया जाता है कि,—

(क) सहायकी का संबंध निर्यात कार्य से है ;

(ख) सहायकी का संबंध निर्यात वस्तु में आयातित माल के बढ़ने परेलू माल के उपयोग से है ; या

(ग) सहायकी, वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात करने में लगे हुए व्यक्तियों की सीमित संख्या को प्रदान की गई है जब तक कि ऐसी कोई सहायकी—

(i) विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात करने में लगे हुए व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से संचालित अनुसंधान क्रिया-कलापों के लिए है ;

(ii) निर्यातक देश के राज्यक्षेत्र के भीतर पिछड़े हुए क्षेत्रों की सहायता करने के लिए है ; या

(iii) नई पर्यावरण संबंधी अपेक्षाओं के लिए विद्यमान सुविधाओं के अनुकूलन का संवर्धन करने में सहायता करने के लिए है ।

(4) यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि अपेक्षाकृत अल्प अवधि में संवत् या प्रवत् सहायकी से फायदा प्राप्त करने वाली वस्तु के प्रति आयात से परेलू उद्योग को ऐसी क्षति हुई है जिसकी क्षतिपूर्ति करना कठिन है और यदि ऐसी क्षति की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए भूतलक्षी रूप से प्रतिशुल्क उद्गृहीत करना आवश्यक है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी तारीख से, जो उपधारा (2) के अधीन प्रतिशुल्क के अधिरोपण की तारीख से पहले की हो किन्तु उस उपधारा के अधीन अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन से परे की न हो, प्रतिशुल्क उद्गृहीत कर सकेगी और तत्समय प्रवत् किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा शुल्क, ऐसी तारीख से संदेय होगा जो इस उपधारा के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) इस धारा के अधीन प्रभार्य प्रतिशुल्क, इस अधिनियम या तत्समय प्रवत् किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(6) इस धारा के अधीन अधिरोपित प्रतिशुल्क, यदि पहले ही प्रतिसंहत नहीं किया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की, किसी पुनर्विलोकन में, यह राय है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से सहायकी और क्षति के जारी रहने की या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि का समय-समय पर, पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी और ऐसी अतिरिक्त अवधि, ऐसे विस्तारण के आवेदन की तारीख से प्रारंभ होगी :

परंतु यह धोर कि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले आरंभ किए गए किसी पुनर्विलोकन का ऐसी समाप्ति से पहले कोई परिणाम नहीं निकला है वहां प्रतिशुल्क, ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम निकलने तक, एक वर्ष से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(7) ऐसी किसी सहायकी की रकम, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभिनिश्चित और अवधारित की जाएगी और केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी वस्तुओं की पहचान करने के लिए और इस धारा के अधीन उसके आयात पर अधिरोपित किसी प्रतिशुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए नियम बना सकेगी।

(8) इस धारा के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

पाटित वस्तुओं पर
प्रतिपाटन शुल्क।

अक. (1) जहां किसी देश या राज्यक्षेत्र से (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् निर्यात करने वाला देश या राज्यक्षेत्र कहा गया है) कोई वस्तु अपने प्रसामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात की जाती है वहां भारत में ऐसी वस्तु का आयात करने पर केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रतिपाटन शुल्क, जो ऐसी वस्तु के संबंध में पाटन अन्तर से अधिक नहीं होगा, अधिरोपित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी वस्तु के संबंध में, “पाटन अन्तर” से उसकी निर्यात कीमत और उसके प्रसामान्य मूल्य के बीच का अंतर अभिप्रेत है ;

(ख) किसी वस्तु के संबंध में, “निर्यात कीमत” से निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र से निर्यात की गई वस्तु की कीमत अभिप्रेत है और उन वशाओं में जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या निर्यातकर्ता और आयातकर्ता या किसी तीसरे पक्षकार के बीच सहयोजन या किसी प्रतिकरात्मक ठहराव के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है वहां निर्यात कीमत का अर्थ ऐसी कीमत के आधार पर लगाया जा सकेगा जिस पर आयात की गई वस्तु का पहली बार पुनर्विक्रय किसी स्वतंत्र क्रेता को किया जाता है या यदि ऐसी वस्तु का पुनर्विक्रय किसी स्वतंत्र क्रेता को नहीं किया जाता है या उस दशा में पुनर्विक्रय नहीं किया जाता है जिसमें वह आयात की गई थी तो, ऐसे युक्तियुक्त आधार पर लगाया जा सकेगा जो उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित किया जाए ;

(ग) किसी वस्तु के संबंध में, “प्रसामान्य मूल्य” से अभिप्रेत है—

(i) व्यापार के मामूली अनुक्रम में वैसे ही वस्तु की जब वह निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र में उपभोग के लिए है, उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित तुल्य कीमत ; या

(ii) जब निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र के बरेलू बाजार में व्यापार के मामूली अनुक्रम में वैसे ही वस्तु का कोई विक्रय नहीं है अथवा जब निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र के बरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति के कारण या विक्रय की कम मात्रा के कारण ऐसे विक्रय से उचित तुलना नहीं की जा सकती है तब प्रसामान्य मूल्य—

(क) वैसे ही वस्तु की जब उसका निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र से अथवा किसी समुचित तीसरे देश से निर्यात किया जाता है तब, ऐसी तुल्य प्रतिनिधि कीमत होगी जो उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित की जाए; या

(ख) प्रशासनिक, विक्रय और साधारण लागत के लिए तथा लाभों के लिए युक्तियुक्त परिवर्धन सहित उद्भव के देश में उक्त वस्तु की ऐसी उत्पादन लागत होगी, जो उपधारा (6) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित की जाती है।

परन्तु उद्भव के देश से भिन्न किसी देश से वस्तु के आयात की दशा में और जहां वस्तु का निर्यातक देश के माध्यम से केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन, निर्यातक देश में नहीं किया गया है अथवा निर्यातक देश में कोई तुल्य कीमत नहीं है वहां, प्रसामान्य मूल्य का अवधारण उद्भव के देश में उसकी कीमत के प्रति निर्देश से किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार, किसी वस्तु के संबंध में उसके प्रसामान्य मूल्य और उसके पाटन अन्तर का अवधारण किए जाने तक, भारत में ऐसी वस्तु के आयात किए जाने पर ऐसे मूल्य और अन्तर के अन्तिम प्राक्कलन के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित कर सकेगी और यदि ऐसा प्रतिपाटन शुल्क इस प्रकार अवधारित अन्तर से अधिक हो जाता है तो—

(क) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अवधारण को ध्यान में रखते हुए और ऐसे अवधारण के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क को कम करेगी; और

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क के उतने भाग का प्रतिदाय किया जाएगा जो इस प्रकार कम किए गए प्रतिपाटन शुल्क के आधिक्य में संगृहीत किया गया है।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार की, जांच के अधीन पाटित वस्तु की बाबत, यह राय है कि—

(i) पाटन का ऐसा इतिवृत्त रहा है जिससे क्षति हुई है या आयातकर्ता को इस बात का ज्ञान था या रहना चाहिए था कि निर्यातकर्ता पाटन करता रहा है और ऐसे पाटन से क्षति होगी; और

(ii) अपेक्षाकृत अल्प समय में आयात की गई वस्तु के क्षति पाटन से क्षति हुई है, जिससे आयात की गई पाटित वस्तु के समय और मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उद्ग्रहण किए जाने के लिए बायीं प्रतिपाटन शुल्क के उपचारी प्रभाव का, गंभीर रूप से जर्जरित होना संभाव्य है,

तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी तारीख से, जो उपधारा (2) के अधीन प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख से पहले की हो, किन्तु उस उपधारा के अधीन अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन से परे की न हो, सूतलक्षी रूप से प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत कर सकेगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा शुल्क, ऐसी दर से और ऐसी तारीख से संदेय होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) इस धारा के अधीन प्रभार्य प्रतिपाटन शुल्क, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(5) इस धारा के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क, यदि पहले ही प्रतिशत नहीं किया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की, किसी पुनर्विलोकन में, यह राय है कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जाड़ी रहने की या उसकी

पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि का समय-समय पर, पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तार कर सकेगी और ऐसी अतिरिक्त अवधि, ऐसे विस्तारण के आदेश की तारीख से प्रारम्भ होगी :

परन्तु यह और कि जहां पांच वर्ष की पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्रारम्भ किए गए किसी पुनर्विलोकन का ऐसी समाप्ति से पहले कोई परिणाम नहीं निकला है वहां प्रतिपादन शुल्क, ऐसे पुनर्विलोकन का परिणाम निकलने तक, एक वर्ष से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(6) पाटन का अन्तर, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अभितिष्ठित और अवधारित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी, और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, ऐसी रीति का, जिससे ऐसी वस्तु की जो इस धारा के अधीन किसी प्रतिपादन शुल्क के लिए दायी है, पहचान की जा सकेगी और ऐसी रीति का, जिससे ऐसी वस्तुओं की निर्यात कीमत और प्रसामान्य मूल्य तथा उनके संबंध में पाटन अन्तर अवधारित किया जा सकेगा, और ऐसे प्रतिपादन शुल्क के निर्धारण और संग्रहण का, उपबंध किया जा सकेगा ।

(7) इस धारा के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

9ख. (1) धारा 9 या धारा 9क में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई वस्तु, पाटन या निर्यात सहायकी की वैसी ही स्थिति के प्रतिकर के लिए प्रतिशुल्क और प्रतिपादन शुल्क दोनों के अधीन नहीं होगी ;

(ख) केन्द्रीय सरकार, किसी प्रतिशुल्क या प्रतिपादन शुल्क का उद्ग्रहण,—

(i) धारा 9 या धारा 9क के अधीन ऐसे शुल्क या करों से ऐसी वस्तुओं पर छूट के कारण, जो वैसी ही वस्तु द्वारा तब वहन किया जाता है जब वह उद्भव के देश या निर्यातक देश में उपभोग के लिए आश्रयित हो अथवा ऐसे शुल्क या करों के प्रतिदाय के कारण नहीं करेगी ;

(ii) धारा 9 और धारा 9क में से किसी की भी उपधारा (1) के अधीन, विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश से या किसी ऐसे देश से जिसके साथ भारत सरकार का कोई परममित्र राष्ट्र करार है (जिसे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट देश कहा गया है), किसी वस्तु के भारत में आयात पर नहीं करेगी जब तक कि इस धारा की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यह अवधारित नहीं किया गया हो कि ऐसी वस्तु का भारत में आयात किया जाता है, भारत में किसी स्थापित उद्योग को तात्त्विक क्षति पहुंचाता है या खतरा उत्पन्न करता है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में तात्त्विक गति-रोध उत्पन्न करता है ; और

(iii) धारा 9 और धारा 9क में से किसी की भी उपधारा (2) के अधीन, विनिर्दिष्ट देशों से किसी वस्तु के भारत में आयात पर नहीं करेगी जब तक कि इस धारा की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, सहायकी या पाटन का और घरेलू उद्योग को उससे पारिणामिक क्षति होने का कोई आरम्भिक परिणाम नहीं निकला हो, और यह अतिरिक्त अवधारण भी किया गया हो कि अन्वेषण के दौरान होने वाली क्षति का निवारण करने के लिए, कोई शुल्क आवश्यक है :

कतिपय मामलों में धारा 9 या धारा 9क के अधीन किसी उद्ग्रहण का न किया जाना ।

परन्तु इस खंड के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब किसी ऐसे तीसरे देश के जो वैसी ही वस्तुओं का भारत को निर्यात कर रहा है, परेशू उद्योग की क्षति का या क्षति के खतरे का निवारण करने के लिए किसी ऐसी वस्तु पर प्रतिशुल्क या प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया गया है :

(ग.) केन्द्रीय सरकार,—

(i) किसी भी समय, निर्यात करने वाले देश या राज्यक्षेत्र की सरकार से सहायकी को समाप्त या परिसीमित करने, अथवा उसके प्रभाव से संबंधित अन्य रक्षणोपाय करने के लिए सहमत होने का समाधानप्रव स्वैच्छिक बचनबन्ध प्राप्त होने पर अथवा निर्यातकर्ता के वस्तु की कीमत का पुनरीक्षण करने के लिए सहमत होने पर, और यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सहायकी का क्षतिकारक प्रभाव तद्वारा समाप्त हो गया है तो, धारा 9 के अधीन किसी प्रतिशुल्क का उद्ग्रहण नहीं कर सकेगी ;

(ii) किसी भी समय, किसी निर्यातकर्ता से उद्युकी कीमतों का पुनरीक्षण करने या प्रश्नगत क्षेत्र को पाटन कीमतों पर निर्यात बन्द करने के लिए, समाधानप्रव स्वैच्छिक बचनबन्ध प्राप्त होने पर और यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी कार्रवाई से पाटन का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है तो, धारा 9क के अधीन किसी प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, ऐसी रीति का, जिससे इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई अन्वेषण किया जा सकेगा, उन बातों का, जिनका ऐसे किसी अन्वेषण में ध्यान रखा जाएगा और ऐसे सभी विषयों का, जो ऐसे अन्वेषण से संबंधित है, उपबन्ध किया जा सकेगा ।

अ. (1) किसी वस्तु के आयात से संबंधित किसी सहायकी या पाटन संबंधी अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव के बारे में, अवधारण के आदेश या उसके पुनर्विलोकन के विरुद्ध अपील, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकरण कहा गया है) हो सकेगी ।

अपील ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपीलाधीन आदेश की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी :

परन्तु अपील अधिकरण, उक्त नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था ।

(3) अपील अधिकरण, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी पुष्टि, उसका उपांतरण या उसे बातिल करते हुए उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझता है ।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129ग की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबन्ध अपील अधिकरण को, इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसको लागू होते हैं ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित विशेष न्यायपीठ द्वारा सुनी जाएगी और ऐसा न्यायपीठ अध्यक्ष तथा कम से कम दो सदस्यों से मिलकर बनेगा और उसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होगा ।” ।

निरसन और
व्याप्ति ।

3. (1) सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अध्यादेश, 1994 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

1994 का अध्या-
देश संख्यांक 14

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 8)

[25 मार्च, 1995]

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,
1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का
अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का
अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ।

(2) यह 21 जनवरी, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 का संशोधन

1970 का 5

2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
की धारा 3 की उपधारा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत-स्थापित
की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 3 का
संशोधन।

“(2खख) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, ‘उपधारा
(1) के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नये बैंक का समावृत्त पूंजी को,
समय-समय पर और उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन लोक निर्गमन
द्वारा समावृत्त पूंजी के जुटाए जाने के पूर्व,—

(क) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्,
ऐसी समावृत्त पूंजी को, जिसकी हानि हुई है, या जो उपलब्ध प्राप्तियों
के रूप में विद्यमान नहीं है, रद्द करके, घटा सकेगी।

(ख) निदेशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करके के पक्षपात और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसी किसी समादत्त पूँजी को, जो तत्स्थानी नये बैंक की आवश्यकताओं से अधिक है, वापस भुगतान करके, घटा सकेगा :

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहाँ किसी अन्य तत्स्थानी नये बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में परिभाषित किसी तत्स्थानी नए बैंक का तत्स्थानी नये बैंक के साथ समामेलन किए जाने के कारण पूँजी की हानि हुई है या जो उपलब्ध आस्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है वहाँ ऐसी कमी भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप में की जा सकेगी किन्तु ऐसे समामेलन की तारीख से पूर्वतर तारीख से नहीं ।

(2खखक) (क) कोई तत्स्थानी नया बैंक, समय-समय पर, और उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूँजी के जुटाये जाने के पश्चात्, ऐसे संकल्प द्वारा, जो मत देने के हकदार शेयर धारकों के वार्षिक साधारण अधिवेशन में, स्वयं या उस दशा में जहाँ परोक्षी अनुज्ञात है वहाँ परोक्षी द्वारा मत लेकर पारित किया जाए, और जहाँ संकल्प के पक्ष में, डाले गए मतों की संख्या, उन मतों की, यदी कोई हो, संख्या के तीन गुने से कम नहीं है, जो ऐसा करने के लिए हकदार और मत देने वाले शेयर धारकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं, अपनी समादत्त पूँजी को किसी भी रूप में घटा सकेगा ।

(ख) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समादत्त पूँजी में, —

(i) किसी ऐसी शेयर पूँजी के संबंध में, जो समादत्त नहीं है, उसके किसी शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर;

(ii) किसी ऐसी समादत्त पूँजी को, जिसकी हानि हुई है, या जो उपलब्ध आस्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है, उसके किसी शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटा कर अथवा निर्वापित किए बिना या घटाए बिना रद्द करके;

(iii) किसी ऐसी समादत्त शेयर पूँजी को, जो तत्स्थानी नए बैंक की आवश्यकताओं से अधिक है, उसके किसी समादत्त शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्वापित किए बिना या घटाए बिना, वापस भुगतान करके,

कमी की जा सकेगी ;

(2खखख) उपधारा (2खख) या उपधारा (2खखक) में किसी बात के होते हुए भी, किसी तत्स्थानी नये बैंक की समादत्त पूँजी में, किसी भी समय, इतनी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि वह बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1995 के प्रारंभ की तारीख को उस बैंक की समादत्त पूँजी के पञ्चीस प्रतिशत से कम हो जाए ।”

अध्याय 3

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)

अधिनियम, 1980 का संशोधन

1980 का 40

3. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

धारा 3 का संशोधन ।

“(2खख) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक की समादत्त पूंजी को, समय-समय पर, और उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाये जाने के पूर्व,—

(क) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक से परामर्श करने पश्चात्, ऐसी समादत्त पूंजी को, जिसकी हानि हुई है, या जो उपलब्ध आस्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है, रद्द करके, घटा मकेगी;

(ख) निर्देशक बोर्ड, रिजर्व बैंक से परामर्श करने पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, ऐसी किसी समादत्त पूंजी को, जो तत्स्थानी नए बैंक की आवश्यकताओं से अधिक है, वापस भुगतान करके घटा मकेगी;

1970 का 5

परन्तु किसी ऐसी दशा में जहां किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (ण) में परिभाषित किसी तत्स्थानी नए बैंक का तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन किए जाने के कारण पूंजी की हानि हुई है या जो उपलब्ध आस्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है या वहां उस कमी को भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से किया जा सकेगा किन्तु ऐसे समामेलन की तारीख से पूर्वतर तारीख से नहीं ।

(2खखक) (क) कोई तत्स्थानी नया बैंक, या समय-समय पर, लोक उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अधीन लोक निर्गमन द्वारा समादत्त पूंजी के जुटाए जाने के पश्चात्, संकल्प द्वारा, जो मत देने के हकदार शेयर धारकों के वार्षिक साधारण अधिवेशन में, स्वयं उस दशा में, या जहां परोक्षी अनुज्ञान है वहां परोक्षी द्वारा, मत देकर पारित किया जाय, और जहां संकल्प के, पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, उन मतों की यदि कोई हो, संख्या के, तीन गुने से कम नहीं है और मत देने वाले शेयर धारकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध डाले गए हैं, अपनी समादत्त पूंजी को किसी भी रूप में घटा मकेगा ।

(ख) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना; समादत्त पूंजी में,

(i) किसी ऐसी शेयर पूंजी के संबंध में जो समादत्त नहीं है, उसके किसी शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर,

(ii) किसी ऐसी समादत्त पूंजी को, जिसकी हानि हुई है, या जो उपलब्ध आस्तियों के रूप में विद्यमान नहीं है, उसके किसी शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्वापित किए बिना या घटाए बिना, रद्द करके;

(iii) किसी ऐसी समादत्त शेयर पूंजी को, जो तत्स्थानी नए बैंक की आवश्यकताओं से अधिक है, उसके किसी समादत्त शेयर पर के दायित्व को निर्वापित करके या घटाकर अथवा निर्वापित किए बिना, घटाए बिना वापस भुगतान करके,

कमी की जा सकेगी ।

(2खखख) उपधारा (2खख) या उपधारा (2खखक) में किसी बात के होते हुए भी, किसी तत्स्थानी नए बैंक की समावृत्त पूंजी में, किसी भी समय, इतनी कटौती नहीं की जाएगी जिससे कि वह बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अधिनियम, 1995 के प्रारंभ की तारीख को उस बैंक की समावृत्त पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से कम हो जाए।”।

अध्याय 4

निरसन और व्यावृत्ति

निरसन और
व्यावृत्ति।

4. (1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

1995 का अध्या-
देश संख्यांक 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

1970 का 5
1980 का 40

राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 26)

[16 जून, 1995]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त नाम।

1956 का 48

2. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8 के पश्चात् निम्न-लिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

नई धारा 8क और धारा 8ख का अन्तःस्थापन।

“8क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, किसी सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग का विकास और अनुरक्षण करने के संबंध में, किसी व्यक्ति से करार कर सकेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए करार करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

(2) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उसके द्वारा की गई सेवाओं या दी गई प्रसुविधाओं के लिए ऐसी दर से फीस के संग्रहण और प्रतिधारण के लिए हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रवर्तन में अन्तर्बलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, उचित प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट करे।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे करार की विषय-वस्तु के भाग रूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर उसके उचित प्रबन्ध के लिए मोटर-यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 8 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार यातायात का विनियमन और नियंत्रण करने की शक्तियां होंगी।

1988 का 94

8ख. जो कोई, किसी ऐसे कार्य द्वारा रिष्टि करेगा, जिससे धारा 8क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को यात्रा या सम्पत्ति प्रवहण के लिए अगम्य या कम निरापद बना दिया जाए या बना दिया जाना वह सम्भाव्य जानता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।”।

राष्ट्रीय राजमार्ग को क्षति पहुंचाने वाली रिष्टि के लिए दण्ड।

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 31)

[22 अगस्त, 1995]

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम,
1979 का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1995 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1979 का 24

2. संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) बृहत् नाम में, "18 दिसम्बर, 1989 की दूसरी रिपोर्ट" शब्द और प्रकों के स्थान पर "25 नवम्बर, 1994 की रिपोर्ट" शब्द और प्रक रखे जाएंगे। बृहत् नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, "पैतालीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "साढ़े सैतालीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"3. 1 अप्रैल, 1995 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष और उत्तरवर्ती चार वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के दौरान, भारत की संचित निधि में से उस वर्ष में उद्घूहीत और संगृहीत वितरणीय संघ उत्पाद-शुल्क के समतुल्य राशियां राज्यों को संदत्त की जाएंगी और—

(क) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियों का सोलह बड़ा उन्नीस भाग, नीचे की सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उसके स्तम्भ (2) में उसके सामने दिया गया है; और

(ख) प्रत्येक ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार संदेय राशियों का तीन बड़ा उन्नीस भाग, नीचे की सारणी 2 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को ऐसे प्रतिशत में वितरित किया जाएगा जो उस वित्तीय वर्ष की बाबत उसके स्तम्भ (2) में उसके सामने दिया गया है।

संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध प्रागमों के भाग के सम-तुल्य राशियों का राज्यों को संदाय और उनमें राशियों का वितरण।

सारणी 1

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	8.465
अरुणाचल प्रदेश	0.170
असम	2.784
बिहार	12.861
गोवा	0.180
गुजरात	4.046
हरियाणा	1.238
हिमाचल प्रदेश	0.704
जम्मू-कश्मीर	1.097
कर्नाटक	5.339
केरल	3.875
मध्य प्रदेश	8.290
महाराष्ट्र	6.126
मणिपुर	0.282
मेघालय	0.283
मिजोरम	0.149
नागालैंड	0.181
उड़ीसा	4.495
पंजाब	1.461
राजस्थान	5.551
सिक्किम	0.126
तमिलनाडु	6.637
त्रिपुरा	0.378
छत्तर प्रदेश	17.811
पश्चिमी बंगाल	7.471

सारणी 2

राज्य (1)	वित्तीय वर्ष और प्रतिशत (2)				
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
आन्ध्र प्रदेश	12.069	7.988	0.000	00.000	0.000
अरुणाचल प्रदेश	3.410	4.300	5.871	6.224	6.667
असम	8.543	9.836	11.849	10.748	9.290
बिहार	6.434	2.965	0.000	0.000	0.000
गोवा	0.973	1.058	1.181	0.917	0.604
हिमाचल प्रदेश	8.816	10.744	14.057	14.230	14.338
जम्मू - कश्मीर	13.366	16.491	21.985	22.741	23.700
मणिपुर	3.930	4.891	6.602	6.917	7.348
मेघालय	3.590	4.403	5.815	5.994	6.130
मिजोरम	3.676	4.628	6.278	6.784	7.074
नागालैण्ड	5.818	7.417	10.247	11.072	12.025
उड़ीसा	4.815	5.248	4.934	2.773	0.680
राजस्थान	0.835	0.000	0.000	0.000	0.000
सिक्किम	1.199	1.473	1.938	1.982	2.055
त्रिपुरा	5.465	6.807	9.263	9.618	10.089
उत्तर प्रदेश	17.061	11.751	0.000	0.000	0.000"।

1995 का अध्या-
देश संख्यांक 9

5. (1) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और
व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्या 32)

[22 अगस्त, 1995]

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल)

अधिनियम, 1957 का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1995 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1957 का 58

2. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) वृद्ध नाम में, "18 दिसम्बर, 1989 की दूसरी रिपोर्ट" श्रृंखला और शब्दों के स्थान पर, "25 नवम्बर, 1994 की रिपोर्ट" श्रृंखला और शब्द रखे जाएंगे।

वृद्ध नाम का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

द्वितीय अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

"द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अतिरिक्त शुल्क का वितरण

1 अप्रैल, 1995 को और उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक को, प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित माल की बाबत, उस वित्तीय वर्ष के दौरान उद्गृहीत और संगृहीत अतिरिक्त शुल्क के शुद्ध भागों में से, उक्त भागों के 2.203 प्रतिशत के बराबर राशि काटकर जो संघ राज्य क्षेत्रों से हुई मानी जा सकती है, उतने प्रतिशत दिया जाएगा जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उसके सामने वर्णित है:

परन्तु यदि उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राज्य में प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (3) में वर्णित माल के विक्रय या क्रय पर अथवा उस राज्य की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उनमें से एक या अधिक माल पर कोई कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन उस राज्य को कोई भी राशियाँ तब तक संदेय नहीं होंगी जब तक केन्द्रीय सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निदेश न दे।

सारणी

राज्य	प्रतिशत
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.820
अरुणाचल प्रदेश	0.104
असम	2.483
बिहार	7.944
गोवा	0.232
गुजरात	6.995
हरियाणा	2.366
हिमाचल प्रदेश	0.595
जम्मू-कश्मीर	0.856
कर्नाटक	5.744
केरल	3.740
मध्य प्रदेश	7.236
महाराष्ट्र	12.027
मणिपुर	0.197
मेघालय	0.188
मिजोरम	0.079
नागालैण्ड	0.137
उड़ीसा	3.345
पंजाब	9.422
राजस्थान	4.873
सिक्किम	0.053
तमिलनाडु	7.669
त्रिपुरा	0.286
उत्तर प्रदेश	14.573
पश्चिमी बंगाल	8.036''

4 (1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरासत किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

निरसन और व्यावृत्ति।

1995 का अध्यादेश संख्यांक 10

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 34)

[30 अगस्त, 1995]

बोनस संदाय अधिनियम, 1965
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1995 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1965 का 21

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (13) में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में, "एक हजार छह सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

1995 का अध्यादेश संख्यांक 8

4. (1) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 35)

[30 अगस्त, 1995]

वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य
की संचित निधि में से कतिपय राशियाँ
का संदाय और विनियोग प्राधिकृत
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2)
अधिनियम, 1995 है ।

संक्षिप्त नाम ।

1995 का 14

2. जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनि-
दिष्ट राशियों से अधिक वे राशियाँ, जिनका कुल योग [जिसमें जम्मू-कश्मीर
विनियोग (लेखानुवान) अधिनियम, 1995 की अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनि-
दिष्ट राशियाँ सम्मिलित हैं] बयालीस अरब, बाईस करोड़, इकतालीस लाख,
सैतालीस हजार रुपए होता है, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिदिष्ट सेवाओं की बाबत
उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान
दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी ।

वित्तीय वर्ष 1995-
96 के लिए जम्मू-
कश्मीर राज्य की
संचित निधि में
से 42,22,41,
47,000 रुपए
का दिया जाना ।

3. इस अधिनियम द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से दी और
उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में
बणित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

विनियोग ।

अनुसूची
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुवत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1 साधारण प्रशासन	राजस्व	21,21,40,000	1,53,22,000	22,74,62,000
	पूँजी	9,10,39,000	—	9,10,39,000
2 गृह	राजस्व	2,41,01,23,000	—	2,41,01,23,000
	पूँजी	5,67,83,000	—	5,67,83,000
3 योजना और विकास	राजस्व	3,79,82,000	—	3,79,82,000
	पूँजी	1,71,66,000	—	1,71,66,000
4 सूचना	राजस्व	4,49,15,000	—	4,49,15,000
	पूँजी	56,21,000	—	56,21,000
5 नहराख कार्य	राजस्व	54,11,81,000	—	54,11,81,000
	पूँजी	29,48,93,000	—	29,48,93,000
6 विद्युत विकास	राजस्व	4,36,82,45,000	—	4,36,82,45,000
	पूँजी	2,91,64,74,000	—	2,91,64,74,000
7 शिक्षा	राजस्व	3,34,05,22,000	—	3,34,05,22,000
	पूँजी	16,37,57,000	—	16,37,57,000
8 बिस्व	राजस्व	1,81,74,90,000	4,55,39,28,000	6,37,14,18,000
	पूँजी	1,85,00,000	2,16,86,00,000	2,18,71,00,000
9 संसदीय कार्य	राजस्व	1,67,40,000	5,43,000	1,72,83,000
10 विधि	राजस्व	9,93,99,000	1,70,99,000	11,64,98,000
11 उद्योग और वाणिज्य	राजस्व	39,63,70,000	—	39,63,70,000
	पूँजी	60,12,17,000	—	60,12,17,000
12 कृषि	राजस्व	79,96,45,000	—	79,96,45,000
	पूँजी	64,07,76,000	—	64,07,76,000
13 पशुपालन/भेड़पालन	राजस्व	44,65,66,000	—	44,65,66,000
	पूँजी	11,18,71,000	—	11,18,71,000
14 राजस्व	राजस्व	78,52,35,000	—	78,52,35,000
	पूँजी	2,04,50,000	—	2,04,50,000
15 खाद्य आपूर्ति और परिवहन	राजस्व	43,15,89,000	—	43,15,89,000
	पूँजी	5,53,80,29,000	—	5,53,80,29,000
16 लोक निर्माण	राजस्व	1,26,06,16,000	—	1,26,06,16,000
	पूँजी	68,43,86,000	—	68,43,86,000

1	2	3		
		₹०	₹०	₹०
17 स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान शिक्षा	राजस्व	1,48,12,83,000	—	1,48,12,83,000
	पूँजी	26,78,91,000	—	26,78,91,000
18 समाज कल्याण	राजस्व	27,91,49,000	—	27,91,49,000
	पूँजी	4,29,59,000	—	4,29,59,000
19 आवास और शहरी विकास	राजस्व	26,57,39,000	—	26,57,39,000
	पूँजी	62,41,95,000	—	62,41,95,000
20 पर्यटन	राजस्व	10,15,68,000	—	10,15,68,000
	पूँजी	13,12,45,000	—	13,12,45,000
21 वन	राजस्व	45,92,91,000	—	45,92,91,000
	पूँजी	26,21,02,000	—	26,21,02,000
22 सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	राजस्व	60,94,99,000	—	60,94,99,000
	पूँजी	39,74,88,000	—	39,74,88,000
23 लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल प्रदाय	राजस्व	75,33,00,000	—	75,33,00,000
	पूँजी	47,24,43,000	—	47,24,43,000
24 संपदा, आतिथ्य और न्यायाचार तथा भाग और उद्योग	राजस्व	13,71,20,000	—	13,71,20,000
	पूँजी	2,73,00,000	—	2,73,00,000
25 श्रम, लेखन सामग्री और मुद्रण	राजस्व	10,70,32,000	—	10,70,32,000
	पूँजी	17,65,51,000	—	17,65,51,000
26 मत्स्य उद्योग	राजस्व	4,23,34,000	—	4,23,34,000
	पूँजी	2,28,57,000	—	2,28,57,000
27 उच्चतर शिक्षा	राजस्व	51,06,16,000	—	51,06,16,000
	पूँजी	12,69,73,000	—	12,69,73,000
योग :		35,46,86,55,000	6,75,54,92,000	42,22,41,47,000

विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 36)

[30 अगस्त, 1995]

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक जितनी रकम व्यय की गई है उनकी पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से धनराशियों का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 1995 है ।

संक्षिप्त नाम ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों के बारे में जिनका कुल योग एक अरब, उनचास करोड़, अठहत्तर लाख, पैंतीस हजार, नौ सौ बीस रुपए होता है, यह समझा जाएगा कि वे उन सेवाओं की बाबत उन प्रभारों को षुकाने के लिए जो अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई रकम की, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, पूर्ति के लिए वी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई है ।

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि में से 1,49,78,35,920 रुपए का दिया जाना ।

3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से वी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई हैं ।

विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3	अनधिक राशियां		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		अनुदान भाग	भारित भाग	योग
			रु०	रु०	रु०
1	कृषि	पूँजी	—	18,700	18,700
14	वाक सेवाएं	राजस्व	21,46,46,092	—	21,46,46,092
15	दूर संचार सेवाएं	पूँजी	25,53,86,487	—	25,53,86,487
18	रक्षा सेवाएं—सेना	राजस्व	53,23,42,445	—	53,23,42,445
22	रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	पूँजी	21,29,09,329	—	21,29,09,329
25	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	4,77,09,052	—	4,77,09,052
33	पेंशन	राजस्व	15,87,71,514	—	15,87,71,514
75	सड़क	पूँजी	6,46,66,261	—	6,46,66,261
95	बाहरा और नागर हवेली	पूँजी	2,58,912	—	2,58,912
97	चंदीगढ़	राजस्व	1,11,77,128	—	1,11,77,128
योग :			1,49,78,17,220	18,700	1,49,78,35,920

विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, 1995

(1995 का अधिनियम संख्यांक 37)

[30 अगस्त, 1995]

वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए भारत की
संचित निधि में से कृतिपय और राशियों का संवाय
और विनियोग प्राधिकृत
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित है :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 4) अधिनियम, संक्षिप्त नाम ।
1995 है ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट वर्ष 1995-96
राशियों में अतिरिक्त वे राशियाँ, जिनका कुल योग चवालीस अरब, इक्कीस करोड़, के लिए भारत की
चालीस लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो अनुसूची संचित निधि में से
के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान 44,21,40,00,
दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी । 000 रुपए का
दिया जाना ।

3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी जाने और उप-
योजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में
वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी ।

विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2	3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		संसद् द्वारा अनुवत्त	संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1 कृषि	राजस्व	1,20,00,00,000	—	1,20,00,00,000
5 रसायन और पेट्रोसायन विभाग	राजस्व	45,02,00,000	—	45,02,00,000
6 उर्वरक विभाग	राजस्व	7,01,00,000	—	7,01,00,000
	पूंजी	2,31,50,00,000	—	2,31,50,00,000
9 नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता कार्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	राजस्व	32,00,00,000	—	32,00,00,000
14 दूरसंचार विभाग	राजस्व	7,01,00,000	—	7,01,00,000
15 रक्षा मंत्रालय	राजस्व	10,00,00,000	—	10,00,00,000
26 वित्तीय संस्थाओं को सहाय	पूंजी	21,92,54,00,000	—	21,92,54,00,000
35 प्रत्यक्ष कर	पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
39 स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	1,00,000	2,00,00,000	2,01,00,000
	पूंजी	1,00,000	—	1,00,000
40 परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	1,00,000	—	1,00,000
46 शिक्षा विभाग	राजस्व	8,17,73,00,000	—	8,17,73,00,000
48 संस्कृति विभाग	राजस्व	10,01,00,000	—	10,01,00,000
50 औद्योगिक विकास विभाग	राजस्व	25,00,00,000	6,00,000	25,06,00,000
51 भारी उद्योग विभाग	राजस्व	55,00,00,000	—	55,00,00,000
	पूंजी	41,96,00,000	—	41,96,00,000
53 लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग	राजस्व	3,93,00,000	—	3,93,00,000
56 श्रम मंत्रालय	राजस्व	10,00,00,000	—	10,00,00,000

1	2	3	4
भारत—	रु०	रु०	रु०
भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व —	1,76,00,000	1,76,00,000
61 खान मंत्रालय	राजस्व 20,00,00,000	—	20,00,00,000
70 ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व 5,50,00,00,000	4,00,000	5,50,04,00,000
72 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व 12,50,00,000	—	12,50,00,000
73 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व 3,00,00,000	—	3,00,00,000
75 इस्पात विभाग	राजस्व 30,00,00,000	—	30,00,00,000
76 जल भूतल परिवहन	राजस्व 22,00,00,000	—	22,00,00,000
77 मङ्गल	राजस्व 15,00,000	—	15,00,000
	पूँजी 1,00,000	—	1,00,000
78 पत्तन, प्रकाश स्तंभ और पोत परिवहन	राजस्व 2,85,00,000	—	2,85,00,000
79 वस्त्र मंत्रालय	राजस्व 55,00,00,000	—	55,00,00,000
	पूँजी 1,07,90,00,000	—	1,07,90,00,000
80 शहरी विकास और आवासन	पूँजी 1,00,00,000	32,00,000	33,00,000
81 लोक निर्माण	पूँजी 2,00,000	3,00,000	5,00,000
83 जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व 5,00,00,000	—	5,00,00,000
योग :	14,17,19,00,000	4,21,00,000	44,21,40,00,000

अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का अधिनियम संख्यांक 15)

[16 दिसम्बर, 1995]

अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986
का संशोधन करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसंधान और विकास उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1995 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1986 का 32

2. अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,—

धारा 2 का
संशोधन।

1995 का 44

(i) खंड (क) से खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख जाएंगे, अर्थात् —

“(क) “बोर्ड” से प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के अधीन गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) “उपकर” से धारा 3 के अधीन उद्गृहीत उपकर अभिप्रेत है ;”।

(ii) खंड (ङ) के अन्त में आने वाले “केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है” शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“समय-समय पर प्रवृत्त भारत सरकार की प्रौद्योगिकी नीति के अनुसार, अनुमोदित किया जाता है या अपने आप ही अनुमोदित हो जाता है।”।

धारा 4 का
संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(i) “विकास बैंक” शब्दों के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) “निधि के प्रयोजनों के लिए” शब्दों के स्थान “बोर्ड के प्रयोजनों के लिए” शब्द रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 और धारा 6 का खोप किया जाएगा।

धारा 5 और
धारा 6 का
खोप।
धारा 8 और
धारा 9 का
संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 में, “विकास बैंक” शब्दों के स्थान पर, जहाँ-जहाँ वह आते हैं, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा।

के० एल० मोहनपुरिया

सचिव, भारत सरकार।

